वर्ष 12 • अंक 254 • 16 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 12 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 4

मोबाइल फोन और कपड़ों पर बढ़ेगा जीएसटी!

आर सी भार्गव ▸▸ पृष्ठ 2

मारुति को पेट्रोल मॉडलों से उम्मीद

डॉलर रु. 70.80 ▼ 10 पैसे | यूरो रु. 78.60 (अपरिवर्तित) | सोना (10ग्राम) रु. 37641 ▲ 26 रुपये | सेंसेक्स 40412.60 ▲ 172.70 | निफ्टी 11910.20 ▲ 53.40 | निफ्टी फ्यूचर्स 11938.20 ▲ 28.00 | ब्रेंट क्रूड 65.10 डॉलर ▼ 0.20 डॉलर

एक नज़र

नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी

नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को संसद ने बुधवार को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने कई घंटों तक चली बहस के बाद से इसे 105 के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे सोमवार को ही मंजूरी दे थी। इस विधेयक के कानून बनने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ होगा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल का भारत के मुसलमानों की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है और उन्हें इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पृष्ठ 16

एडीबी ने घटाया भारत का वृद्धि दर अनुमान

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5 फीसदी से घटाकर बुधवार को 5.1 फीसदी कर दिया। एडीबी ने वृद्धि के अनुमान घटाने के अधार के बारे में कहा कि नौकरियों के अवसर सृजित होने की रफ्तार कम हुई है तथा फसलों के खराब होने और कर्ज की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव की स्थिति बिगड़ी है। एडीबी के अनुसार की बदहाल स्थिति तथा रोजगार की धीमी वृद्धि दर ने उपभोग को प्रभावित किया है। इसके कारण वृद्धि दर के अनुमान को घटाया गया है। एडीबी ने सितंबर में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 के लिए 6.5 फीसदी और 2020-21 में 7.2 फीसदी रहने का अनुमान व्यक्त किया था। उसने कहा कि वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 6.5 फीसदी रह सकती है। पृष्ठ 4

येस बैंक का शेयर 15 फीसदी लुढ़का

निजी क्षेत्र के ऋणदाता येस बैंक की दो अरब डॉलर की पूंजी जुटाने की योजना पर अनिश्चितता के कारण बुधवार को इसका शेयर 15 फीसदी से अधिक लुढ़क गया। येस बैंक के शेयर में लगातार पांचवें दिन गिरावट आई है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर येस बैंक का शेयर सुबह गिरावट के साथ खुला और कारोबार के दौरान एक समय 19.48 फीसदी लुढ़ककर 40.70 रुपये पर आ गया। कारोबार की समाप्ति पर यह 15.33 फीसदी की गिरावट के साथ 42.80 रुपये पर बंद हुआ। मंगलवार को भी येस बैंक का शेयर 10 फीसदी टूटा था।

पाठकों से

पृष्ठ 3 पर 'इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज' के बारे में प्रायोजित परिशिष्ट है। इसके लेखन में बिज़नेस स्टैंडर्ड के किसी पत्रकार की भूमिका नहीं है। इसे विज्ञापन के रूप में ही लें।

आज का सवाल

क्या आईबीसी में संशोधन से समाधान प्रक्रिया में आएगी तेजी

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या राजकोषीय घाटे का लक्ष्य चूक जाएगी सरकार? हां **44.44%** नहीं **56.56%**

धनी प्रवर्तकों की संख्या घटी मगर शीर्ष 10 की हैसियत बढ़ी

कृष्ण कांत
मुंबई, 11 दिसंबर

अर्थव्यवस्था में व्यापक उथल-पुथल ने भारतीय अरबपति प्रवर्तकों की रैंकिंग भी बदल दी है। कई दिग्गज और पुराने अरबपति पीछे छूट गए, वहीं कुछ कम चर्चित अरबपति शीर्ष प्रवर्तकों की सूची में जगह बनाने में सफल रहे। निजी क्षेत्र की शीर्ष कंपनियों में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी के बाजार मूल्य में बदलाव से पता चलता है कि मार्च 2018 में उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद से अरबपति प्रवर्तकों की संख्या घटी है, वहीं धनाढ्य और अपेक्षाकृत कम धनाढ्य प्रवर्तकों के बीच का अंतर 2019 में बढ़ा है।

देश के दस धनी प्रवर्तकों (नेटवर्थ के आधार पर) की संपत्ति अब करीब 180 अरब डॉलर हो गई है जो एक साल पहले 140 अरब डॉलर था। इसके उलट हमारी सूची में शामिल 10 अपेक्षाकृत कम धनी अरबपतियों की संपत्ति में औसतन 20 फीसदी की कमी आई है। इन दस प्रवर्तकों की कुल नेटवर्थ करीब 10.5 अरब डॉलर है, जो एक साल पहले 13 अरब डॉलर थी। शेयर भाव में गिरावट की वजह से पिछले 12 महीने में इन प्रवर्तकों की नेटवर्थ में करीब 22 फीसदी की कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप शीर्ष दस धनी प्रवर्तकों के पास देश में कुल प्रवर्तक संपत्ति का करीब 41.2 फीसदी है, जो दिसंबर 2018 के अंत में 32.5 फीसदी और मार्च 2018 में 28 फीसदी थी। इसके साथ ही एक अरब डॉलर या उससे अधिक हैसियत वाले प्रवर्तकों की संख्या अब 80 रह गई है जो दिसंबर 2018 में 82 थी।

यह विश्लेषण नमूने में शामिल 822 कंपनियों में प्रवर्तक हिस्सेदारी और बाजार पूंजीकरण के आधार पर किया गया है। नमूने में सरकारी कंपनियों, वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की

दस शीर्ष धनी प्रवर्तकों की देश में कुल प्रवर्तक संपत्ति में है 41 फीसदी हिस्सेदारी, जो दिसंबर 2018 में थी 33 फीसदी

सूचीबद्ध इकाइयों, संस्थान के स्वामित्व वाली कंपनियों और उनकी सहायक इकाइयों जैसे कि एलऐंडटी, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक आदि शामिल नहीं हैं। नमूने में होल्डिंग कंपनियों की अलग से सूचीबद्ध सहायक इकाइयों जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बॉम्बे बर्मा, रिलायंस कैपिटल, बजाज फिनसर्व, गोदरेज इंडस्ट्रीज और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा आदि को भी समायोजित किया गया है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड के नमूने में शामिल 574 प्रवर्तकों में से केवल 142 की बाजार हैसियत 6 दिसंबर 2019 को बंद भाव के आधार पर 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक थी। इसके साथ ही 432 प्रवर्तकों के नेटवर्थ में कमी आई है। दिसंबर 2018 के बाद से कुल प्रवर्तक की शुद्ध हैसियत 3.2 फीसदी बढ़ी है, लेकिन इसका लाभ बड़ी कंपनियों को अधिक मिला है। भारत की शीर्ष कंपनियों के मालिकों की हैसियत अब करीब 31 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो एक साल पहले 30.2 लाख करोड़ रुपये थी। भारती एयरटेल के प्रवर्तक सुनील मित्तल और उनके परिवार की शुद्ध हैसियत पिछले साल दिसंबर के मुकाबले 83 फीसदी बढ़ी है। यह इजाफा तब हुआ है जब दूरसंचार क्षेत्र बेहद दबाव में दिख रहा है। फिलहाल करीब 62,000 करोड़ रुपये के साथ मित्तल परिवार देश का 10वां सबसे धनी परिवार है। मित्तल परिवार ने सन फार्मा के दिलीप सांघवी, डाबर के बर्मन, गोदरेज परिवार और कुमार मंगलम बिड़ला सहित कई दूसरे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है।

रुपये में दर्ज बढ़त के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी सूची में सबसे ऊपर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अंबानी के परिवार की हिस्सेदारी चालू कैलेंडर वर्ष में 21.2 अरब डॉलर या 47 फीसदी बढ़कर 68 अरब डॉलर हो गई, जो एक साल पहले 46.4 अरब डॉलर थी।

इसके बाद अदाणी समूह के गौतम अदाणी का नाम आता है, जिनके परिवार की शुद्ध परिसंपत्ति 24 फीसदी या 3.5 अरब डॉलर हो गई। समूह की प्रमुख कंपनियों जैसे अदाणी पोर्ट्स ऐंड सेज, अदाणी पावर, अदाणी गैस और अदाणी ट्रांसमिशन में भी पिछले 12 महीनों में मजबूत तेजी दिखी है। दिलचस्प है कि कुछ एकल लेकिन सफल कारोबार विभिन्न कारोबार में लगी कंपनियों के मुकाबले अधिक धनी हो गए हैं। उदाहरण के लिए बंधन बैंक के सी एस घोष, डी-मार्ट के आर के दमानी और श्री सीमेंट के बांगुर अब परंपरागत उद्योगपतियों जैसे कुमार मंगलम बिड़ला, आदि गोदरेज और वेदांत के अनिल अग्रवाल से आगे निकल गए हैं।

आईबीसी की अंतिम बाधा दूर!

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता में संशोधन को दी मंजूरी

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 11 दिसंबर

आर्सेलर मित्तल, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियों के रास्ते से अंतिम अड़चन दूर करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) में संशोधनों को मंजूरी दे दी। इसके तहत अगर किसी कॉरपोरेट कर्जदार का आईबीसी के तहत सफल समाधान हो चुका है तो पिछले प्रबंधन या प्रवर्तक द्वारा किए गए किसी भी अपराध के लिए अधिग्रहणकर्ता पर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी। सरकार को इस बारे में जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील जैसी कंपनियों की तरफ से कई ज्ञापन मिले थे। उनका कहना था कि आईबीसी प्रक्रिया के पूरी होने के बाद उनके सामने कई अड़चनें आ रही हैं।

पीडब्ल्यूसी इंडिया में पार्टनर अंशुल जैन ने कहा, 'अधिग्रहणकर्ता कंपनियां लंबे समय से इस राहत की मांग कर रही थीं। यह बराबरी का सिद्धांत को स्थापित करता है। इससे अधिग्रहणकर्ता को संरक्षण मिलेगा। कॉरपोरेट कर्जदार के पिछले प्रवर्तकों और निदेशकों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अधिग्रहणकर्ता पर कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी। इस तरह वे बिना किसी देनदारी के परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर सकेंगे। अगर अधिग्रहणकर्ता किसी परिसंपत्ति के लिए भुगतान करता है तो उसे देनदारी रहित परिसंपत्ति मिलनी चाहिए।'

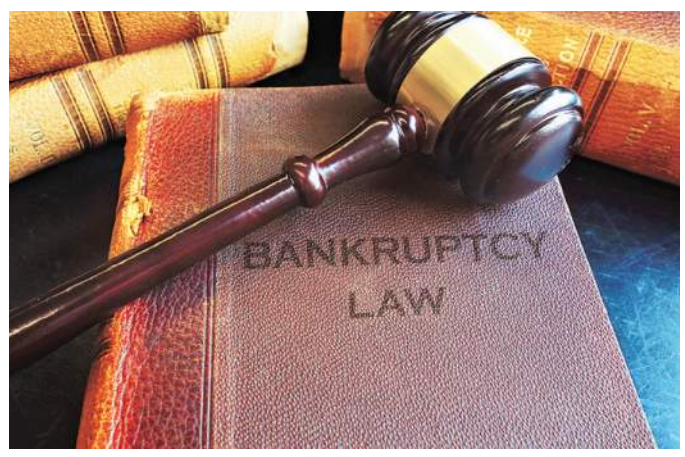

- **पिछले प्रबंधन के अपराधों के लिए अधिग्रहणकर्ता पर नहीं होगी कार्यवाही**
- **टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू ने की थी राहत की मांग**

टाटा स्टील बीएसएल (पहले भूषण स्टील) ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि कंपनी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई एक कार्यवाही का सामना करना पड़ा जो 50 लाख रुपये की अस्थायी कुर्की आदेश की पुष्टि से जुड़ा था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कंपनी के पिछले प्रबंध निदेशक पर लगे अवैध भुगतान के आरोप के तहत यह राशि जब्त की थी। कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स में पार्टनर मनोज कुमार ने कहा, 'सरकार ने आईबीसी में बहुत जरूरी संशोधन किए हैं। आईबीसी प्रक्रिया को निवेशकों और अधिग्रहणकर्ता के लिए आकर्षक बनाने के वास्ते इसकी बहुत जरूरत थी। जिन कंपनियों का आईबीसी के तहत समाधान हो चुका है उसके अधिग्रहणकर्ता पर पिछले प्रबंधन के अपराधों के लिए कार्रवाई नहीं होगी।'

जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी भूषण पावर ऐंड स्टील की समाधान योजना के संबंध में नियामकीय संस्थाओं से राहत की मांग की थी। अलबत्ता, राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) ने कोई राहत दिए बिना 19,350 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दी थी। कंपनी ने एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपील की है। जेएसब्ल्यू ने अपनी अपील में कहा है कि संरक्षण के अभाव में और आपराधिक कार्यवाहियों के कारण पैदा हुई देनदारी से वह समाधान योजना लागू करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी क्योंकि ऐसा करना अव्यावहारिक होगा।

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने आईबीसी में इस संशोधन को भी मंजूरी दी है कि कर्ज स्थगन अवधि के दौरान कॉरपोरेट कर्जदार के लाइसेंस, परमिट, रियायत और मंजूरी को खत्म या निलंबित नहीं किया जाएगा और न ही इनका नवीनीकरण किया जाएगा। इससे सुनिश्चित किया गया है कि कॉरपोरेट कर्जदार के कारोबार का आधार कमजोर न पड़े और उसका व्यवसाय जारी रहे।

■ संबंधित खबर : पृष्ठ 4

आंशिक क्रेडिट योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना पर मुहर लगा दी। योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के साथ ही अब सरकारी बैंक वित्तीय रूप से सुदृढ़ इकाइयों से जमा परिसंपत्तियां खरीद सकते हैं। इस योजना का लाभ केवल एक बार मिलेगा और 30 जून तक या 1,00,000 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियां बैंकों के खरीदे जाने तक तक योजना जारी रहेगी। योजना की प्रगति के मद्देनजर वित्त मंत्री इसकी अवधि 3 महीने तक के लिए बढ़ा सकती हैं।

अदाणी की वितरण इकाई में हिस्सा लेगी क्यूआईए

अमृता पिल्लै
मुंबई, 11 दिसंबर

अदाणी ट्रांसमिशन ने अपने मुंबई के बिजली वितरण कारोबार में 25.1 फीसदी हिस्सेदारी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (क्यूआईए) को 3,200 करोड़ रुपये में बेचने का आज करार किया। अदाणी ट्रांसमिशन ने इस कारोबार को अगस्त 2018 में खरीदा था और दो साल से भी कम समय में वह मुंबई बिजली वितरण कारोबार को बेचने जा रही है।

अदाणी ट्रांसमिशन ने कहा, 'उसकी सहायक इकाई अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई (एईएमएल) और क्यूआईए की एक सहायक इकाई ने इस सौदे के लिए बाध्यकारी समझौता किया है। एईएमएल में 25.1 फीसदी हिस्सेदारी क्यूआईए को बेचने के लिए करार किया है।'

अगस्त 2018 में अदाणी ट्रांसमिशन ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर से 12,100 करोड़ रुपये में मुंबई बिजली वितरण कारोबार खरीदा था। इस कारोबार का संचालन वर्तमान में सहायक इकाई एईएमएल के तहत किया जा रहा है। 25.1 फीसदी हिस्सेदारी 3,200 करोड़ रुपये में बेचा जा रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि कंपनी मुनाफे में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है।

समझौते के तहत मुंबई वितरण कारोबार के लिए 30 फीसदी बिजली की आपूर्ति स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से करनी होगी। एटीएल और क्यूएआई के पास 2023 से 30 फीसदी से अधिक बिजली की आपूर्ति सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्रों से करने की सुनिश्चित योजना है। इस सौदे के 2020 की शुरुआत में पूरा होने की उम्मीद है, जो नियामकीय मंजूरी और संतोषजनक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, 'हमारा मानना है कि यह सौदा क्यूआईए के साथ दीर्घावधि के साझेदारी की शुरुआत की दिशा में अदाणी समूह का महत्त्वपूर्ण कदम है।' हिस्सेदारी बेचने के पीछे क्या रणनीति है, इस बारे में जानकारी के लिए अदाणी ट्रांसमिशन को ईमेल भेजा गया लेकिन जवाब नहीं आया।

एक विश्लेषक ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, 'कंपनी का पारेषण एवं वितरण कारोबार के लिए मौजूदा वित्तपोषण की जरूरतें बिना किसी विनिवेश के पूरी हो सकती हैं। हिस्सेदारी बेचने से मिलने वाली रकम का उपयोग भविष्य में पारेषण कारोबार के अधिग्रहण में या अन्य सर्किलों में वितरण के लिए बोली लगाने में किया जा सकता है।'

इस साल अदाणी समूह द्वारा विदेशी निवेशक या कंपनी को हिस्सा बेचने का यह दूसरा मौका है। अक्टूबर में फ्रांस की ऊर्जा कंपनी टोटाल के साथ अदाणी गैस में 37.4 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए करार किया गया था। यह सौदा किसी सॉवरिन फंड द्वारा भारत के बिजली वितरण कारोबार में किया जाने वाला पहला निवेश होगा। क्यूआईए ने संयुक्त बयान में कहा कि विश्व-स्तरीय बुनियादी ढांचा संपत्तियों में भरोसेमंद साझेदारों के साथ क्यूआईए के निवेश शृंखला के तहत यह नवीनतम निवेश है। क्यूआईए के मुख्य कार्याधिकारी मंसूर अल-महमूद ने कहा, 'हम अदाणी समूह के साथ दीर्घावधि की साझेदारी की संभावना देख रहे हैं।'

एसकेएन एडवाइजर्स ने इस सौदे में एटीएल और एईएमएल के लिए वित्तीय परामर्शक और सिरिल अमरचंद मंगलदास ने कानूनी सलाहकार की भूमिका अदा की। जेपी मॉर्गन ने क्यूआईए के लिए वित्तीय सलाहकार और क्लियरी गॉटलीव स्टीन ऐंड हैमिल्टन एलएलपी तथा एजेडबी एवं पार्टनर्स ने कानूनी सलाहकार की भूमिका अदा की।

■ संबंधित खबर : पृष्ठ 12

गौतम अदाणी
चेयरमैन, अदाणी समूह

- **मुंबई बिजली वितरण कारोबार में 25.1 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी**
- **3,200 करोड़ रुपये में हुआ यह सौदा**
- **अगस्त 2018 में अदाणी समूह ने रिलायंस इन्फ्रा से खरीदा था यह कारोबार**

ग्राहक बेखबर, एचपीसीएल बुक कर रही उनका सिलिंडर

उज्ज्वला के उपभोक्ताओं द्वारा सिलिंडर की कम बुकिंग, खुले बाजार में सिलिंडर की बिक्री करने को मजबूर कंपनी

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 11 दिसंबर

सरकारी तेल विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शनों की ऑटो बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी को रसोई गैस सिलिंडरों की कम बुकिंग के कारण आलोचना का सामना करना पड़ रहा था।

उद्योग के सूत्रों के मुताबिक एचपीसीएल ने पीएमयूआई के कम से कम 25 फीसदी उपभोक्ताओं के पहले सिलिंडर की ऑटो-बुकिंग (उपभोक्ताओं की बुकिंग के बिना) की है। इस तरह करीब 50 लाख कनेक्शनों के लिए ऑटो-बुकिंग की गई है। पीएमयूवाई के तहत 8.03 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया गया है। इनमें से दो करोड़ से अधिक उपभोक्ता एचपीसीएल के हैं।

...उज्ज्वला का लेखाजोखा

वर्ष	एलपीजी पहुंच (प्रतिशत)	उज्ज्वला लाभार्थी (करोड़ में)
2015-16	61.9	शून्य
2016-17	72.8	2.03
2017-18	80.9	3.56
2018-19	94.3	7.19
2019-20 (अप्रैल-सितंबर)	96.5	8.03

स्रोतः पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

एक आधिकारिक सूत्र ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ऑटो-बुकिंग आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा है और लोगों को जागरूक बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि इस बारे में कंपनी के प्रवक्ता ने ईमेल से भेजी गई प्रश्नावली का कोई जवाब नहीं दिया।

फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर्स ऑफ इंडिया के महासचिव पवन सोनी ने कहा, 'एचपीसीएल सिलिंडरों की ऑटो-बुकिंग कर रही है जिससे वितरकों को भी परेशानी हो रही है। कई उपभोक्ता सिलिंडर लेने को तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने इसे बुक नहीं किया है।' राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की पिछले महीने आई एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में देश के केवल 61 फीसदी परिवारों ने खाना बनाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल किया। एक अन्य वितरक ने कहा, 'ऑटो बुक किए गए जिन सिलिंडरों की आपूर्ति नहीं हो रही है, उनसे एक फर्जी बैकलॉग बन रहा है। इससे वितरक की स्टार रेटिंग प्रभावित हो रही है जिससे उन पर भारी जुर्माना लग रहा है और कुछ मामलों में तो लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं।' जुर्माने के डर से कुछ वितरक इन सिलिंडरों को खुले बाजार में बेचने को मजबूर हैं। इससे जबरन रसोई गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है और एलपीजी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत जमा सब्सिडी का दुरुपयोग हो रहा है। सिलिंडरों के ऑटो-बुकिंग के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि डीबीटी का पैसा तो लाभार्थी के खाते में जा रहा है जबकि सिलिंडर का इस्तेमाल कोई और कर रहा है। सरकार के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में एलपीजी सब्सिडी पर 32,989 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक पीएमयूवाई के कम से कम 87 फीसदी लाभार्थियों ने कम से कम दूसरी बार सिलिंडर भरा है।

सिलिंडरों की कम बुकिंग की समस्या के समाधान के लिए तेल विपणन कंपनियों ने 14.2 किलो के सिलिंडर को 5 किलो के सिलिंडर से बदलने की सुविधा शुरू की है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

खबरों में रहे स्टॉक

अदाणी ट्रांसमिशन

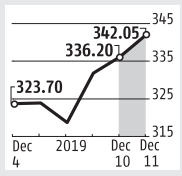

अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में 25.1 फीसदी हिस्सेदारी कतर इन्वेस्टमेंट को बेची

₹ 336.20 पिछला बंद भाव
₹ 342.05 आज का बंद भाव
▲ 1.74 %

येस बैंक

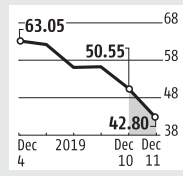

बोर्ड ने नए निवेशकों पर घोषणा टाली

₹ 50.55 पिछला बंद भाव
₹ 42.80 आज का बंद भाव
▼ 15.33 %

गेल (इंडिया)

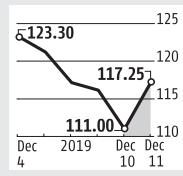

एसऐंडपी बीएसई 100 सूचकांक में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 111.00 पिछला बंद भाव
₹ 117.25 आज का बंद भाव
▲ 5.63 %

सीएसबी बैंक

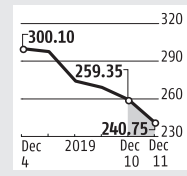

लगातार पांचवें दिन गिरावट, सूचीबद्ध होने के बाद 21 फीसदी गिरा शेयर

₹ 259.35 पिछला बंद भाव
₹ 240.75 आज का बंद भाव
▼ 7.17 %

डीएलएफ

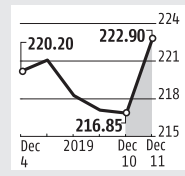

बाजार पूंजीकरण बढ़कर 55,174 करोड़ रुपये हुआ

₹ 216.85 पिछला बंद भाव
₹ 222.90 आज का बंद भाव
▲ 2.79 %

संक्षेप में

अरामको ने 10 फीसदी बढ़त से की शुरुआत

सउदी अरामको के शेयर का बाजार में तेजी के साथ स्वागत किया गया। कंपनी के रिकॉर्ड 25.6 अरब डॉलर के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के बाद इसका शेयर बुधवार को स्थानीय शेयर बाजार में पहले दिन के कारोबार की शुरुआत में 10 फीसदी की बढ़त पर था। इससे कंपनी की बाजार में शेयर मूल्य के हिसाब से हैसियत 1,880 अरब डॉलर तक पहुंच गई। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से यह विश्व की सबसे महंगी सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। अरामको ने आईपीओ की दर 32 रियाल यानी 8.53 डॉलर प्रति शेयर तय की थी और प्राथमिक बाजार में शेयर बेच कर 25.6 अरब डॉलर जुटाए। *भाषा*

एलऐंडटी फाइनैंस जुटाएगी 1,500 करोड़ रुपये

एलऐंडटी फाइनैंस गैर परिवर्तनीय ऋण-पत्र (एनडीसी) की बिक्री के जरिए 1,500 करोड़ रुपये जुटा रही है। कंपनी इस राशि का इस्तेमाल ऋण वितरण तथा मौजूदा कर्ज की किस्तें चुकाने में करेगी। कंपनी ने बुधवार को कहा कि इस इश्यू का मूल आकार 500 करोड़ रुपये है। इसमें एक हजार करोड़ रुपये तक जुटाने का विकल्प भी खुला रखा गया है। कंपनी ने कहा कि पहली खेप में 36 महीने, 60 महीने और 84 महीने की परिपक्वता वाले एनडीसी की पेशकश की जा रही है। इनपर 8.25 से 8.65 प्रतिशत का ब्याज दर है। *भाषा*

मारुति को पेट्रोल मॉडलों से उम्मीद

डीजल श्रेणी से बाहर होने के बावजूद बाजार हिस्सेदारी और बिक्री पर भरोसा

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 11 दिसंबर

कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया को अपने पोर्टफोलियो में डीजल मॉडलों के न होने के बावजूद बिक्री और बाजार हिस्सेदारी बरकरार रहने की उम्मीद है। कंपनी का मानना है कि उसके बीएस6 पेट्रोल और सीएनजी मॉडलों की बिक्री बढ़ेगी। जबकि उसकी प्रमुख प्रतिस्पर्धी कंपनी हुंडई की नजर बीएस6 उत्सर्जन मानदंड लागू होने पर 1 अप्रैल 2020 से कॉम्पैक्ट सिडैन श्रेणी में अपना एकाधिकार कायम करने पर है।

यात्री वाहन की अधिकतर श्रेणियों में पेट्रोल मॉडलों को पसंद किए जाने से मारुति का विश्वास बढ़ा है। जापान की प्रमुख वाहन कंपनी सुजूकी की घरेलू इकाई ने जून 2019 में डीजल श्रेणी से बाहर होने की घोषणा की थी। कंपनी ने बीएस4 डीजल इंजन को बीएस6 इंजन में बदलने की लागत अधिक होने के कारण यह फैसला लिया था।

मारुति के कार्यकारी निदेशक (बिक्री एवं विपणन) शशांक श्रीवास्तव ने कहा, 'यदि आप यात्री वाहन की विभिन्न श्रेणियों में पेट्रोल और डीजल की हिस्सेदारी पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि पेट्रोल की हिस्सेदारी अधिक है।' मारुति ने आज मुंबई में डीलर और खुदरा वित्त पोषण के लिए फेडरल बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

श्रीवास्तव ने कहा कि वैन का बाजार पूरी तरह पेट्रोल चालित है। हैचबैक श्रेणी में डीजल की हिस्सेदारी फिलहाल महज 5 फीसदी है जबकि कुल यात्री वाहन बाजार में उसकी हिस्सेदारी 46 फीसदी है। उन्होंने कहा कि सिडैन श्रेणी में डीजल वाहनों की हिस्सेदारी 30 से 35 फीसदी है जबकि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) श्रेणी में डीजल वाहनों की हिस्सेदारी 67 से 68 फीसदी है।

एसयूवी श्रेणी में प्रवेश एवं मझोले स्तर पर पेट्रोल की हिस्सेदारी अधिक है। एमजी हेक्टर और सेल्टॉस जैसे नए मॉडलों के लिए करीब 75 फीसदी बुकिंग पेट्रोल के लिए हुई है जबकि कीया के लिए 55 फीसदी बुकिंग पेट्रोल से आती है। श्रीवास्तव ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि लोगों का रुझान अब पेट्रोल वाहनों की ओर बढ़ने लगा है।

साल 2012 में कुल बिक्री में डीजल की हिस्सेदारी 60 फीसदी थी जो घटकर अब महज 30 फीसदी रह गई है और मारुति के लिए यह आंकड़ा 20 फीसदी से भी कम है। श्रीवास्तव ने कहा कि बीएस6 उत्सर्जन मानदंड लागू होने पर डीजल और पेट्रोल मॉडलों के बीच मूल्य संबंधी अंतर बढ़ जाएगा और ऐसे में डीजल की हिस्सेदारी घटेगी।

डीजल श्रेणी से मारुति के बाहर होने से उसके निवेशक चिंतित नहीं हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष मितुल शाह ने कहा, 'हमें बिक्री और बाजार हिस्सेदारी पर उसका कोई खास असर नहीं दिखता है।' एक अन्य विश्लेषक ने कहा कि यदि बिक्री में गिरावट हुई तो 5 फीसदी से अधिक नहीं होगी क्योंकि डीजल श्रेणी में मारुति का निवेश कम है। मारुति ने उम्मीद जताई है कि ब्रेजा और एस-क्रॉस के बीएस6 पेट्रोल वेरिएंट डीलज की गैर मौजूदगी को भरपाई करेगी।

रफ्तार रहेगी बरकरार

- यात्री वाहन की अधिकतर श्रेणियों में पेट्रोल मॉडलों को पसंद किए जाने से मारुति का विश्वास बढ़ा
- हैचबैक श्रेणी में डीजल की हिस्सेदारी महज 5 फीसदी है जबकि कुल यात्री वाहन बाजार में उसकी हिस्सेदारी 46 फीसदी

नवंबर में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 1 फीसदी बढ़ी

एजेंसियां
नई दिल्ली , 11 दिसंबर

त्योहारी मांग से यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री नवंबर में 1 फीसदी बढ़कर 2,57,271 वाहन हो गई। जबकि नवंबर 2018 में 2,55,535 यात्री वाहनों की बिक्री हुई थी।

वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने कहा है कि नवंबर 2019 में दोपहिया वाहनों की बिक्री 3 फीसदी बढ़कर 17,05,495 वाहन हो गई। नवंबर 2018 में यह आंकड़ा 16,60,082 वाहनों का था। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 8 फीसदी घटकर 77,394 इकाई रही जो एक साल पहले नवंबर महीने में 84,040 इकाई पर थी। तिपहिया वाहनों की बिक्री 20 फीसदी बढ़कर 65,348 वाहन हो गई। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों में वाहनों की कुल बिक्री 2 फीसदी बढ़कर 21,05,508 वाहन हो गई। एक साल पहले नवंबर महीने में यह आंकड़ा 20,54,296 वाहनों का था।

फाडा के अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले ने कहा कि मॉनूसन के बाद अब कृषि उपज बाजारों में आना शुरू हो गई है। जिसने कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री बढ़ाने में योगदान दिया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार की ओर से किए सकारात्मक उपायों ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।

मर्सिडीज 3 फीसदी तक बढ़ाएगी कीमत

लक्जरी कार कंपनी मर्सिडीज-बेंज इंडिया लागत बढ़ने के कारण जनवरी से अपने वाहनों के दाम 3 फीसदी तक बढ़ाने वाली है। कंपनी ने बुधवार को इसकी घोषणा की। निसान मोटर इंडिया, मारुति सुजूकी, हुंडई मोटर और टाटा मोटर्स जैसी अन्य वाहन निर्माता कंपनियां भी जनवरी से वाहनों के दाम बढ़ाने वाली हैं।

निसान 5 फीसदी तक बढ़ाएगी कीमत

निसान मोटर इंडिया ने बुधवार को कहा कि वह अगले महीने से अपने वाहनों की कीमतें 5 फीसदी तक बढ़ाने वाली है। कंपनी ने कहा कि निर्माण की लागत में हुई वृद्धि के असर को कम करने के लिए उसे वाहनों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं।

बिक्री बढ़ाने के लिए विपणन रणनीति दुरुस्त कर रही सेल

अदिति दिवेकर
मुंबई, 11 दिसंबर

सरकारी इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) मात्रात्मक बिक्री में पिछले महीने यानी नंवबर में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 36 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। गोदामों की बेहतर उपयोगिता, बेहतर ब्रांडिंग रणनीति और विपणन पर बारीकी नजर से कंपनी को बिक्री बढ़ाने में मदद मिली। आर्थिक नरमी के कारण घरेलू बाजार में कमजोर मांग संबंधी चिंताओं के बीच कंपनी ने नवंबर में 14.09 लाख टन इस्पात की बिक्री की।

कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'सितंबर में हमने अपनी विपणन इकाई का पुनर्गठन किया था। उसी पुनर्गठन का नतीजा अब दिखने लगा है।' कंपनी ने अपने विपणन विभाग को तीन श्रेणियों- बिक्री, विपणन एवं सेवा- में बांटा है ताकि कारोबार पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित किया जा सके।

अधिकारी ने कहा, 'विभागों को विभिन्न श्रेणियों में बांटने से विपणन में सूक्ष्म प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त हुआ और हरेक क्षेत्र बेहतर परिणाम के लिए कारोबार पर गंभीरतापूर्वक ध्यान केंद्रित करता है।' सेल ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि नवंबर के लिए कंपनी का बिक्री आंकड़ा उद्योग में बेहतरीन भी रहा है जो बाजार में मौजूद अवसरों को भुनाने के लिए दमदार विपणन रणनीति को दर्शाता है। कंपनी की विपणन इकाई मूल्य निर्धारण, ब्रांडिंग और प्रमोशन पर ध्यान केंद्रित कर रही है जबकि बिक्री इकाई की नजर गोदाम और वस्तुओं की आवाजाही पर है। दूसरी ओर, सेवा इकाई की नजर लॉजिस्टिक्स और ग्राहक सेवा पर बरकरार रहेगी।

खुदरा विपणन में सेल का सामना काफी हद तक डीलरों से होता है। कंपनी अब बाजार में वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए अपने वितरण नेटवर्क को दमदार बनाने की कोशिश कर रही है। एक अधिकारी ने कहा, 'हमने वितरकों के लिए 47 जगहों की पहचान की है और उनमें से 27 जगह देश के पूर्वी भागों में हैं जहां हमारे संयंत्र मौजूद हैं। चूंकि यह हमारा स्वाभाविक बाजार है और इसलिए अन्य क्षेत्रों के मुकाबले यहां हमें बेहतर प्राप्तियां मिल सकती हैं। इससे खुदरा बाजार में हमारे उत्पाद की बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी।'

घरेलू बाजार के प्राथमिक इस्पात उत्पादकों में सेल के पास डीलरों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। कंपनी अपने गोदामों का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को भी प्रोत्साहित करती है। कंपनी इस सेवा के लिए स्टॉकयार्ड मार्जिन के तौर पर 600 रुपये प्रति टन की दर से कमाई करती है। जबकि सीधे तौर पर आपूर्ति के मामले में ऐसा नहीं होता है।

अधिकारी ने कहा, 'गोदामों के इस्तेमाल का अपना फायदा है क्योंकि ग्राहक टुकड़ों के भुगतान कर सकते हैं जबकि सीधी आपूर्ति में के मामले में ऐसा कोई विकल्प नहीं होता। साथ ही यदि गुणवत्ता संबंधी कोई समस्या आती है तो गोदाम प्रणाली के तहत ग्राहकों के पास माल न उठाने का विकल्प होता है लेकिन सीधी आपूर्ति के मामले में ग्राहकों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं होती। ग्राहक पूरी आपूर्ति होने के बाद ही गुणवत्ता संबंधी कोई मुद्दा उठा सकता है।'

फिलहाल देश भर में सेल के पास कुल 45 गोदाम मौजूद हैं जिनमें से कुछ गोदाम कंपनी के स्वामित्व वाले हैं जबकि शेष का स्वामित्व एक एजेंसी के पास है।

आपूर्ति समय के संदर्भ में सेल ने ट्रकों के लिए समय को 2 से 3 घंटे कम कर दिया जो पहले 10 घंटे से अधिक था।

बीएस बातचीत

'अगले त्योहारी सीजन से दिखेगी वास्तविक वृद्धि'

पिछले एक साल से वाहनों की कमजोर बिक्री से वाहनों के लिए फाइनैंस करने वाली कंपनी महिंद्रा ऐंड महिंद्रा फाइनैंशियल सर्विसेज को भी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। कंपनी के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक **रमेश अय्यर** से **श्रीपाद ऑटे** की बातचीत:

हाल में आईएफसी ने आपके एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) कारोबार को रफ्तार देने के लिए 20 करोड़ डॉलर के वित्त पोषण की घोषणा की है। क्या अब आप इस कारोबार पर अधिक ध्यान देंगे?

एसएमई हमारे लिए हमेशा एक महत्त्वपूर्ण इकाई रही है। यह एक नया कारोबार श्रेणी है और आगे यह वृद्धि को संचालित करेगी। लेकिन जहां तक वित्त पोषण का सवाल है तो एक संगठन के तौर पर हम विभिन्न स्रोतों की तलाश करते रहते हैं। आईएफसी उनमें से एक है। यह ईसीबी यानी वाह्य वाणिज्यिक उधारी है जो 8 फीसदी से कम ब्याज दर पर तीन वर्षों के लिए दी गई है। इसलिए इससे कुल परिसंपत्ति-देनदारी प्रबंधन और उधारी लागत प्रभावित होगी।

एसएमई की आय अर्जन क्षमता के बारे में आप क्या कहेंगे?

एसएमई एक थोक कारोबार है और उसका प्रतिफल हमारे 11 से 13 फीसदी के औसत प्रतिफल के अनुरूप है। अच्छी बात यह है कि वाहन कारोबार के विपरीत एसएमई श्रेणी से गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) अधिक नहीं है। हमारी नजर तीन श्रेणियों- वाहन, कृषि और इंजीनियरिंग- पर है और एसएमई उन मौजूदा श्रेणियों में शामिल होंगे जिनके साथ सीधा संबंध होगा। इसलिए हमें नकदी प्रवाह शृंखला और कुल कारोबार की अच्छी समझ होगी।

त्योहारी सीजन के बाद वाहनों की मांग कैसी रही?

इस साल त्योहारी सीजन यानी अक्टूबर अच्छा रहा। नवंबर भी उतना खराब नहीं रहा जितने की उम्मीद की जा रही थी। खुदरा कारोबार अच्छा रहा और इसका मतलब यह साफ है कि डीलरों के पास इन्वेंटरी का स्तर कम हुआ है। मैं समझता हूं कि दिसंबर भी बेहतर रहेगा क्योंकि नए साल के मद्देनजर सभी अपने पुराने मॉडल का स्टॉक खपाना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मात्रात्मक बिक्री के लिहाज से यह तिमाही वित्त वर्ष 2020 में अब तक की बेहतरीन तिमाही होगी।

सुधार कब तक दिखने के आसार हैं?

वित्त वर्ष 2020 की पहली दो तिमाहियों के दौरान तेजी पहले ही दिख रही है। लेकिन वास्तविक वृद्धि करीब 8 से 10 महीने बाद यानी अगले त्योहारी सीजन के बाद दिखेगी। इस साल खरीफ फसल औसत रहने के आसार हैं लेकिन मॉनसून को देखते हुए अगले साल रबी फसल अच्छा रहने की उम्मीद है। इससे धारणा में सकारात्मक बदलाव होगा।

आरकैपिटल ने की ब्याज भुगतान में देरी

रिलायंस कैपिटल ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि उसे गैर-परिवर्तनीय डिवेंचर के मूलधन अथवा ब्याज का भुगतान 9 दिसंबर को करना था जिसमें देरी हो गई है। कंपनी ने कहा है कि केयर रेटिंग ने इस साल सितंबर में कंपनी के पूरे बकाये ऋण को डिफॉल्ट श्रेणी में डाल दिया था जबकि कंपनी पर किसी भी लेनदार के मूलधन अथवा ब्याज भुगतान का बकाया नहीं था। कंपनी को विभिन्न लेनदारों के ऋण का पुनर्भुगतान 2028 तक चरणबद्ध तरीके से करना था। बीएसई पर कंपनी का शेयर आज 4.8 फीसदी गिरावट के साथ 10.90 रुपये पर बंद हुआ। केयर रेटिंग ने कंपनी के बॉन्ड की दीर्घावधि रेटिंग घटाकर उसे डिफॉल्ट श्रेणी में डाल दिया है। *बीएस*

मोबाइल फोन और कपड़ों पर बढ़ेगा जीएसटी!

जीएसटी परिषद राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए उल्टे कर ढांचे को दुरुस्त करने की दिशा में कर रही है काम

दिलाशा सेठ
नई दिल्ली, 11 दिसंबर

जीएसटी परिषद अगले सप्ताह मोबाइल फोन और कपड़े पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर बढ़ा सकती है। परिषद राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए उल्टे कर ढांचे को सही करने की कोशिश कर रही है। तैयार उत्पाद की तुलना में इनपुट पर कर की अधिक दर के ढांचे के कारण बड़ी मात्रा में इनपुट टैक्स क्रेडिट जा रहा है। वे अन्य उत्पाद जिनमें उल्टा कर ढांचा है, उनमें कपड़े के थैले, जूते, ट्रैक्टर आदि शामिल हैं।

मोबाइल फोनों पर जीएसटी की दर 12 फीसदी है, जबकि फोन के कलपुर्जों और बैटरियों पर दर 18 फीसदी है। इसकी वजह से इनमें उल्टा कर ढांचा है। इससे अनुपयोगी इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला पैदा होता है और इसलिए सरकार को रिफंड जारी करना पड़ता है। पिछले साल एक फोन विनिर्माता ने ही करीब 4,100 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया था।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, 'उल्टे कर ढांचे के मसले को हल किया जाना जरूरी है। इससे रिफंड के रूप में बड़ी धनराशि का भुगतान करना पड़ रहा है। मोबाइल फोन, कपड़े और अन्य चीजों पर दरों में संशोधन किया जा सकता है।' एक पंजीकृत करदाता इनपुट पर ज्यादा कर और तैयार उत्पाद पर कम कर के चलते बिना दावा किए गए आईटीसी के रिफंड का दावा कर सकता है।

इसी तरह कपड़े पर जीएसटी की दर पांच फीसदी है, जबकि अलग-अलग तरह के धागों पर 12 फीसदी कर लगता है। शुरुआत में सरकार ने कपड़ा विनिर्माताओं को आईटीसी रिफंड का दावा करने की मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन बाद में जुलाई 2018 की बैठक में रिफंड को मंजूरी दे दी। एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'आईटीसी रिफंड को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। उस समय राजनीति की वजह से यह फैसला लिया गया। अब इसे सही किया जाना चाहिए।'

अगर सभी वित्त मंत्री सहमत हो जाते हैं तो उल्टे कर ढांचे को सही करने के लिए कपड़े पर जीएसटी की दर पांच फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी की जा सकती है। दरअसल केंद्र और कुछ राज्यों के अधिकारियों की एक उप समिति गठित की गई है। यह समिति उन उत्पादों की सूची तैयार करेगी, जिनमें कर का ढांचा उल्टा है। जूतों के मामले में 1,000 रुपये से कम कीमत के जूतों पर कर की दर पांच फीसदी है। वहीं नहीं बुने और चमड़े पर कर 12 फीसदी है। इसी तरह ट्रैक्टर के कलपुर्जों पर कर 28 फीसदी और ट्रैक्टर पर 12 फीसदी है।

डेलॉयट इंडिया में पार्टनर एम एस मणि ने कहा कि उल्टे कर ढांचे को सही करना आवश्यक है। यह स्थिति पिछले दो वर्षों में कई बार दरों में बदलाव के कारण कुछ क्षेत्रों में पैदा हुई है क्योंकि तैयार उत्पादों की दरों में बदलाव को हमेशा इनपुट दरों के साथ समायोजित नहीं किया गया।

इसके विपरीत पीडब्ल्यूसी इंडिया में पार्टनर प्रतीक जैन ने कहा कि ज्यादातर मामलों में उल्टे कर ढांचे की समस्या का समाधान तैयार उत्पादों की दरों को बढ़ाना नहीं है क्योंकि पांच फीसदी और 12 फीसदी के स्लैब में उत्पादों को उनकी अहमियत और आम आदमी पर असर को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। उन्होंने कहा, 'अगर संभव है तो इनपुट उत्पादों की दरों को कम किया जाए। इसके अलावा इनपुट सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी के रिफंड को मंजूरी देना भी एक विकल्प है, जिस पर विचार किया जा सकता है। इस समय रिफंड केवल इनपुट तक सीमित है।'

उल्टे कर ढांचे के कारण सरकार को चुकाना पड़ रहा है मोटा रिफंड

- तैयार उत्पाद की तुलना में इनपुट पर अधिक कर से बड़ी मात्रा इनपुट टैक्स क्रेडिट का करना पड़ रहा है भुगतान
- मोबाइल, कपड़ों, जूतों और ट्रैक्टरों जैसे उत्पादों में है कर का उल्टा ढांचा
- मोबाइल फोनों पर जीएसटी की दर 12 फीसदी है, जबकि फोन के कलपुर्जों और बैटरियों पर दर 18 फीसदी है
- इसी तरह कपड़े पर जीएसटी की दर पांच फीसदी है, जबकि अलग-अलग तरह के धागों पर 12 फीसदी कर लगता है

एडीबी ने घटाया भारत की वृद्धि का अनुमान

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 11 दिसंबर

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान में भारी कमी की है। एडीबी ने 2019-20 में भारत की आर्थिक वृद्धि 5.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया है, जो पहले 6.5 फीसदी अनुमानित था। इसने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में संकट और उपभोग में कमी के कारण वृद्धि का अनुमान घटाया है।

'मददगार' नीतियों की बदौलत यह वृद्धि 2020-21 में बढ़कर 6.5 फीसदी हो जाएगी, लेकिन यह भी एडीबी के पहले के अनुमान 7.2 फीसदी से कम रहेगी। यह वृद्धि अनुमान एडीबी के एशियाई विकास आउटलुक 2019 के पूरक में दिया गया है। इसके चलते चालू वित्त वर्ष में भारत के हाथ से सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा छिन जाएगा और यह तमगा चीन के पास चला जाएगा।

चीन की 2019 में वृद्धि दर 6.1 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि पहले एडीबी ने 6.2 फीसदी का अनुमान जताया था। एडीबी ने कारोबारी गतिविधियों में कमी और कमजोर घरेलू मांग के कारण चीन की वृद्धि का अनुमान घटाया है।

हालांकि, भारत अगले वर्ष फिर से चीन को पीछे छोड़ देगा क्योंकि चीन की वृद्धि दर 2020 में 5.8 फीसदी रहने का अनुमान है जो कि पहले छह फीसदी अनुमानित था।

एडीबी ने 2019-20 में भारत की आर्थिक वृद्धि 5.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया

इकबाल मिर्ची मामले में सात संपत्तियां जब्त

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 11 दिसंबर

आतंकी फंडिंग पर प्रहार करने की कार्रवाई को जारी रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इकबाल मेमन ऊर्फ इकबाल मिर्ची और उसके परिवार से संबंधित 600 करोड़ रुपये की सात से अधिक परिसंपत्तियों को जब्त किया है। ईडी गैंगस्टर के खिलाफ धन शोधन मामले में जांच कर रहा है। एजेंसी ने यह कार्रवाई सोमवार को जांच एजेंसी द्वारा अभियोजन शिकायत दाखिल करने के बाद की है।

जब्त की गई परिसंपत्तियों में वर्ली स्थित सीजे हाउस और ताड़देव स्थित अरुण चैम्बर जैसे वाणिज्यिक भवन शामिल हैं। अन्य परिसंपत्तियो में वर्ली के प्रमुख जगहों पर स्थित साहिल बंगलो, राबिया मैनिसन, मरियम लॉज और सी व्यू शामिल हैं। इसमें क्रॉफोर्ड बाजार में तीन वाणिज्यिक दुकानें और लोनावला में पांच एकड़ का जमीन का टुकड़ा भी शामिल हैं।

ईडी के मुताबिक मिर्ची मुंबई और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में इन परिसंपत्तियों का अप्रत्यक्ष तौर पर मालिक था। जांच के दौरान प्रवर्तन अधिकारियों ने लंदन, दुबई और महाराष्ट्र के मुंबई में इकबाल मिर्ची की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की 30 संपत्तियों की पहचान की थी।

सीजे हाउस के लेनदेन की जानकारी देते हुए ईडी ने कहा कि मिर्ची परिवार के पास इस 15 मंजिला प्रमुख वाणिज्यिक संपत्ति के तीसरे और चौथे मंजिल पर 14,000 वर्गफुट जगह है। इस इमारत को मिलेनियम डेवलपर ने फिर से विकसित किया है। इस स्थान का कुछ हिस्सा पहले एम के मोहम्मद के अधिकार में था। मिर्ची ने 1986 में 9 लाख रुपये में अपनी पत्नी हाजरा मेमन के नाम से संपत्ति में अधिकार खरीदने के लिए मोहम्मद के साथ एक करार किया था। उस सौदे में महज 20,000 रुपये का भुगतान किया गया और उसी वर्ष मेमन ने संपत्ति का कब्जा ले लिया। इस जगह पर मेमन ने फिशरमैन व्हार्फ नाम से डिस्को शुरू किया था। अधिकारी ने बताया कि बाद में जब इस जगह को दोबारा से विकसित कर यहां सीजे हाउस खड़ा किया गया तब उसमें मिर्ची को उसकी पत्नी और बेटों के नाम से दो मंजिल दिए गए।

यह 15 मंजिली इमारत 2006-2007 में मिर्ची और मिलेनियम डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम थी।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता प्रफुल्ल पटेल ईडी की जांच के घेरे में हैं। सीजे हाउस में उनके नाम पर दो फ्लैट हैं और वह मिलेनियम डेवलपर्स प्राइवेट के शेयरधारक भी हैं।

अधिकारी ने कहा कि इसी तरह से अन्य परिसंपत्तियों का भी सौदा किया गया ताकि संपत्ति को खरीदने के लिए रकम की आपराधिक उत्पत्ति को छिपाया जा सके। उदाहरण के लिए साहिल बंगलो को मिर्ची ने अपनी पत्नी और भाई असलम मर्चेंट और बहन जैबुनिसा मेमन नाम पर खरीदा था। उसके बाद दोनों भाई और बहन ने अपने हिस्से की संपत्ति मेमन की पत्नी के नाम कर दिया था।

ईडी का शिकंजा

- ईडी ने इकबाल मिर्ची और उसके परिवार की 600 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां जब्त कीं
- गैंगस्टर के खिलाफ धन शोधन मामले में जांच कर रही है एजेंसी
- प्रवर्तन अधिकारियों ने लंदन, दुबई और मुंबई में मिर्ची की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की 30 संपत्तियों की पहचान की थी

रियल्टी के लिए पीरामल का फंड

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 11 दिसंबर

पीरामल समूह ने कहा है कि उसने 2,000 करोड़ रुपये का वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) शुरू करने के लिए आईआईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट के साथ साझेदारी की है। यह फंड रियल एस्टेट डेवलपरों को परियोजना के अंतिम चरण के लिए धन मुहैया कराएगा। समूह ने कहा कि इस फंड का इस्तेमाल अहम बाजारों में टीयर-1 डेवलपरों को पूंजी मुहैया कराने में किया जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय हुई है, जब हाल में एसबीआईकैप वेंचर्स ने अपने स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल ऐंड मिड इनकम हाउसिंग (एसडब्ल्यूएएमआईएच) निवेश फंड के पहले चरण में 10,530 करोड़ रुपये का फंड मुहैया कराया है। एसडब्ल्यूएएमआईएच फंड की घोषणा हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं के लिए की थी। यह फंड कुल 25,000 करोड़ रुपये का है।

हाल में एडलवाइस समूह ने 42.5 करोड़ डॉलर का फाइनैंसिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया था। समूह ने मौजूदा आवासीय रियल एस्टेट ऋणों को खरीदने और डेवलपरों को परियोजना पूरी करने के लिए ऋण मुहैया कराने की खातिर दक्षिण कोरिया की कंपनी मेरिट्ज फाइनैंशियल ग्रुपके साथ साझेदारी की थी।

रोचक बात यह है कि बुधवार की घोषणा के साथ ही रियल एस्टेट को कर्ज मुहैया कराने में पीरामल की फिर से वापसी हो गई है। पीरामल ने वैश्विक फंडों के साथ गठजोड़ पर ध्यान देने के लिए रियल एस्टेट फंडों से तौबा कर ली थी। समूह ने सीपीपीआईबी आदि के साथ समझौता किया था। रिपोर्टों के मुताबिक इसने ढांचागत ऋण फंड की पहली क्लोजिंग की है।

पीरामल कैपिटल ऐंड हाउसिंग फाइनैंस के एमडी कुशरू जिजिना ने कहा, 'इस एआईएफ का सृजन पीरामल समूह की इस रणनीति की तर्ज पर किया गया है कि अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर ऋण देने के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएं। हम शुरुआत में फंड में धनराशि पीरामल समूह के पोर्टफोलियो के मौजूदा ऋणों से डालेंगे।

पीरामल और आईआईएफएल के फंड से परियोजनाओं को अंतिम चरण के लिए दिया जाएगा धन

रिहायशी क्षेत्रों में फैक्टरियों की सीलिंग में तेजी

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 11 दिसंबर

अनाज मंडी आग हादसे के बाद दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध फैक्टरियों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई अब तेज होगी। पिछले डेढ़ साल से दिल्ली सरकार द्वारा सौंपी गई करीब 52 हजार फैक्टरियों के खिलाफ कार्रवाई की कवायद चल रही हैं, लेकिन अब तक इनका सर्वेक्षण भी पूरा नहीं हो पाया है। अब इस काम में तेजी आने के साथ ही सीलिंग की कार्रवाई जोर पकड़ सकती है।

दिल्ली नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक रिहायशी इलाकों में अवैध फैक्टरियों के खिलाफ सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में है। अब तक इन अवैध फैक्टरियों को पहले सीलिंग के नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन हाल में एनजीटी के उस आदेश के बाद अब बिना नोटिस सीलिंग की कार्रवाई करने की योजना है। एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि अवैध फैक्टरियों को सीलिंग के लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक 52 हजार में से करीब 40 हजार फैक्टरियों का दो चरणों में सर्वेक्षण हो चुका है और तीसरे चरण के तहत करीब 12 हजार फैक्टरियों के खिलाफ सर्वेक्षण और सीलिंग कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने निगम अधिकारियों को इस माह के आखिर तक यह काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डेढ़ साल में रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध फैक्टरियों का सर्वेक्षण पूरा न होने के सवाल पर एक निगम अधिकारी ने कहा कि निगमों के पास सर्वेक्षण करने के लिए लाइसेंस इंसपेक्टरों की भारी कमी है। इसलिए इस काम में देरी हुई है। उत्तरी नगर निगम ने इस वित्त वर्ष अब तक करीब 400, पूर्वी और दक्षिणी नगर निगम ने 100-100 अवैध फैक्टरियों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की है। तीनों निगमों ने हजारों फैक्टरियों को सीलिंग नोटिस भी भेजे हैं, जिन पर अब सीलिंग की कार्रवाई होनी है।

दिल्ली में सीलमपुर, मंडोली, नंद नगरी, गांधीनगर, विश्वास नगर, बदरपुर, तुगलकाबाद, ओखला, जसोला गांव, जामिया व इसके आस पास के इलाके, अलीपुर, बिंदापुर गांव, मटियाला, नजफगढ़, मोरी गेट, करोलबाग, सदर बाजार, नरेला समेत अन्य रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से एक लाख से अधिक अवैध फैक्टरियों के चलने की आशंका है। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2003 से रिहायशी इलाकों में फैक्टरियां बंद होनी थी।

कर्ज लेकर डिस्कॉम की रकम चुकाएगा आंध्र

बी दशरथ रेड्डी
हैदराबाद, 11 दिसंबर

आंध्र प्रदेश सरकार ने एपी पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन (एपीपीएफसीएल) को 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी है। यह पैसा डिस्कॉम को अपनी भुगतान बाध्यताओं को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऋण अधिकतम 8.5 फीसदी ब्याज दर से अधिक पर नहीं लिया जाए।

एपीपीएफसीएल राज्य की बिजली इकाइयों के लिए फंड जुटाने वाली नोडल एजेंसी है जिसके लिए वह बॉन्ड जारी करती है या फिर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण लेती है।

एपीपीएफसी के एक अधिकारी ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'सरकार ने 10,000 करोड़ से 11,000 करोड़ रुपये के ऋण के लिए गारंटी देने का निर्णय लिया है। यह रकम इस साल निगम द्वारा जुटाई जाएगी। डिस्कॉम को अन्य मदों सहित बिजली खरीद के भुगतान के लिए उस रकम की जरूरत है। हम पहले ही सभी बैंकों से 8.5 फीसदी ब्याज दर के भीतर ऋण देने के लिए संपर्क कर चुके हैं।'

निगम ने इस बार ऋणों के रूप में रकम जुटाने का निर्णय लिया है क्योंकि बॉन्ड बाजार में वह प्रतिकूल स्थिति का सामना कर रहा है। अधिकारी के मुताबिक बॉन्ड बाजार के संभावित निवेशक बिजली बॉन्डों पर 11 फीसदी तक रिटर्न की मांग कर रहे हैं।

साल 2018 में एन चंद्रबाबू नायडू की अगुआई वाली पिछली सरकार ने अमरावती राजधानी शहर के लिए 2,000 करोड़ रुपये जुटाई थी जिसके लिए उसने 10.32 फीसदी की तय ब्याज दर पर 10 साल का बॉन्ड जारी किया था। तब विपक्ष ने इसकी लागत को लेकर उस सरकार की आलोचना की थी। लेकिन ऋण लेना वाई एस जगन मोहन रेड्डी सरकार के लिए कोई आसान विकल्प नजर नहीं आ रहा है। एपीपीएफसीएल के 3,000 करोड़ रुपये के ऋण आवेदन पर विचार करते हुए भारतीय स्टेट बैंक की मुंबई शाखा ने सरकार की पुनर्भुगतान क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि, एसबीआई ऋण देने के लिए तैयार हो गया है।

एपीपीएफसीएल के अधिकारी ने कहा, 'कुछ निश्चित शर्तों के साथ एसबीआई निगम को 1,500 करोड़ रुपये देने पर तैयार हो गया जबकि हमने 3,000 करोड़ के ऋण के लिए अनुरोध किया था। बैंक इसके लिए 8.5 फीसदी ब्याज लेगा। सरकार ने ब्याज दर की ऊपरी सीमा 8.5 फीसदी तय की है इसलिए हमने सभी बैंकों को इसी शर्त पर ब्याज देने केलिए पत्र भेजा है।'

संचित बिजली बकाया 20,000 करोड़ रुपये का हो गया है जिसमें करीब 3,000 करोड़ रुपये का बकाया अक्षय ऊर्जा उत्पादकों का है। पिछले महीने राज्य के बिजली मंत्री बलीनेनी श्रीनिवास रेड्डी ने दूसरी बार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह को पत्र लिखकर उनसे अपनी सरकार की मांग दोहराई। इस पत्र के जरिये उन्होंने मांग की है कि केंद्र को अक्षय ऊर्जा की एकीकृत लागतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

बिजली वितरण कंपनियों की सुधरेगी सेहत

- राज्य सरकार ने एपी पावर फाइनैंस कॉर्पोरेशन को 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी
- डिस्कॉम को अन्य मदों सहित बिजली खरीद के भुगतान के लिए 10,000 करोड़ रुपये की जरूरत

एचपीसीएल कर रही ऑटो बुकिंग

पृष्ठ 1 का शेष

एक अधिकारी ने कहा कि पीएमयूवाई के उपभोक्ताओं के फिर से सिलिंडर नहीं भरने की एक मुख्य वजह यह है कि वे रिफिल बुक कराने की प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते हैं और कंपनी ने उन्हें जागरूक बनाने के लिए ऑटो-बुकिंग की प्रक्रिया अपनाई है।पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के पास मौजूद नवंबर के आंकड़ों के मुताबिक देश में एलपीजी के करीब 27.4 करोड़ उपभोक्ता हैं। इनमें से 7.5 करोड़ उपभोक्ता को एचपीसीएल के हैं जबकि इंडियन ऑयल के 12.9 करोड़ और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के करीब 7 करोड़ उपभोक्ता हैं। पीएमयूवाई के आने से पहले 65 फीसदी बुकिंग इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) या एसएमएस के जरिये होती थी।सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 96.5 फीसदी लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन है जबकि 2015-16 में यह संख्या 61.9 फीसदी थी। इस दौरान वितरकों की संख्या में भी 35 फीसदी बढ़ोतरी हुई और यह संख्या 24,127 पहुंच गई। उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी और 5 करोड़ उपभोक्ताओं को मुफ्त कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था। योजना की सफलता को देखते हुए 8 करोड़ उपभोक्ताओं तक विस्तारित करने का फैसला किया गया और इसके लिए 12,800 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया।

बीएस सूडोकू 3610 | परिणाम संख्या 3609

				6		8		1
		1	5		2	4		6
	8	9			4			7
2	5				3	6		
4	1						5	9
		6	2				7	3
9			6			3	4	
1		5	3		7	9		
3		2		9				

9	8	7	5	2	3	4	6	1
1	5	2	4	7	6	9	3	8
3	4	6	1	8	9	2	5	7
7	2	3	8	6	4	5	1	9
6	9	5	7	3	1	8	2	4
4	1	8	2	9	5	6	7	3
8	3	4	6	1	2	7	9	5
5	6	1	9	4	7	3	8	2
2	7	9	3	5	8	1	4	6

कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत आसन ★☆☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2100/2110, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2150/2225, सरसों 4300/4325, तिल सफेद 9400/9600, सोया (टीन) 1450/1500, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1560/1630,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2100/2125, गेहूं शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2900/2975,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1442, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1528, फ्लैक 1458, डीएमओ 1000, टरपीन लैस बोल्ड 1545

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1050/1080, खुरपा 950/970,चाकू 980/1080, रसकट 850/870, शक्कर 1150/1180, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3325, सिहोरा 3165, बुंदकी 3190, बुढ़ाना 3270, शामली 3210,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3500/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 880/900, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4350, खल: सरसों 2250/2350,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5500/5600, गेहूं (मिल) 2140/2150, मक्की 2050/2100, बाजरा 1840/1850, जौ 1800/1850, ग्वार लूज 3800/3825, ज्वार कैटलफीड 2000/2100, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4640/4650,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2000/2050, ग्वार 3600/3650, जौ 2015/2050, सरसों लूज 4000/4025

जोधपुर
गेहूं 2000/2100, जौ 1750/1800, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3900/3950, ग्वारगम 7100/7200, बाजरा (गुजरात) 1900/1910, बाजरा (जयपुर) 1890/1900, चना 4100/4200, काबली चना 4700/5900, मूंग 6000/6100,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)125, राइसब्रान (अखाद्य) 122, खल सरसों 2000, डीओसी: राइसब्रान बेच सफेद 1200, लाल 1200, कंटीन्यूअस 1250,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7500/8000, अरहर दाल 7900/8400, उड़द साबुत 7500/8300, उड़द धोया 9500/10500, छिलका 9000/10000, दाल मसूर 5500/5800, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6000/6100, सेला 5500/5600, शरबती साधारण सेला 3700/3800, शरबती स्टीम 4100/4200,चावल 1509 सेला 5100/5200, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब नई 3950/3980, हरियाणा 3930/3950, राजस्थान 3900/3950, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2300/2400, सरसों खल 2180/2185,

फाजिल्का
गेहूं 2140/2150, सरसों 4350/4400 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3950/4000,कपास देशी 4850/4950, कपास नरमा (क्विं.) 5100/5200, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2300/2400,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2100/2120, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2320/2330, बिहार 2375/2380, दाल उड़द छिलका 9000/11000, चना देशी 5000/5100, दाल चना 5200/5400, काबली चना 4900/5800, राजमां चित्रा पुणे 6800/8300, चीन 7200/7800,

करनाल
गेहूं दड़ा 2140/2150, बासमती चावल 6400/6500, धान 1121 नं. 2850/2900, पूसा 1509 धान 2550/2600, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5250/5300, स्टीम 5800/5900,

हिसार
ग्वार 3750/3800, सरसों 4150/4200, गेहूं 2140/2150, नरमा कपास 5100/5150

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी घी (एक ली/जार) 370/470, चीनी 3480/3550,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4100/4150, खल बिनौला मोटी 2400/2500, बिनौला 2700/3200, सरसों तेल 8850/8900, गेहूं 2100/2200, ग्वार 3800/3850, बाजरा 1800/1900 एनएनएस

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 254

डेटा संरक्षण की चिंता

सरकार ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की सार्वजनिक जांच और संसदीय परीक्षण तक कम करने के लिए अप्रत्याशित उपाय किए हैं। विधेयक के मसौदे को संसद में पेश करने के पहले भलीभांति वितरित नहीं किया गया और मसौदा प्रक्रिया के दौरान की गई टिप्पणियों तथा अन्य बातों को भी सार्वजनिक नहीं किया गया। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने अनुरोध किया कि विधेयक का परीक्षण संसद की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (जिसकी अध्यक्षता एक विपक्षी सदस्य के पास है) से कराने के बजाय इस उद्देश्य के लिए प्रवर समिति से कराई जाए। जांच की इस कमी के चलते ऐसी आशंका उत्पन्न हुई है कि शायद चिंता उत्पन्न करने वाली कई वजहें बरकरार रहें।

सकारात्मक पहलू देखें तो कंपनियों द्वारा डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ अच्छा संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें विलोपन के अधिकार से संबंधित अधिकार के साथ-साथ सुधार के अधिकार का प्रावधान भी है जो लोगों को यह अनुरोध करने का अधिकार देता है कि वे आंकड़ों को मिटा सकें या उनमें बदलाव कर सकें। ऐसा तब किया जा सकेगा जब वह आंकड़ा जिस उद्देश्य से दिया गया था वह पूरा हो चुका हो और उसकी अब आवश्यकता नहीं रह गई हो। हालांकि सरकारी निगरानी और डेटा प्रबंधन के क्षेत्र में भारी भरकम रियायत के जरिये इसे नाकाम कर दिया गया। इसके अलावा भी कई परेशान करने वाले प्रावधान हैं। सोशल मीडिया मंचों से कहा जाएगा कि वे उपयोगकर्ताओं के प्रमाणन की एक स्वैच्छिक प्रक्रिया पेश करें। सरकार का दावा है कि वह ऐसा डेटा मांग सकती है जो व्यक्तिगत न हो। सन 2018 में न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति ने जो मसौदा तैयार किया था उसमें भी सरकार को डेटा प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ रियायतें प्रदान की गई थीं। अब उनका और विस्तार कर दिया गया है। श्रीकृष्ण समिति ने सरकारी डेटा प्रसंस्करण के बारे में सुझाव दिया था कि इसे जरूरी और उचित अनुपात में होना चाहिए। अब यह प्रावधान हटा दिया गया है। बल्कि किसी भी सरकारी संस्था या विभाग को बिना सहमति के डेटा जुटाने का अधिकार देने का प्रावधान शामिल कर दिया गया है। यानी राज्य की निगरानी पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया।

प्रस्तावित डेटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) को कमजोर कर दिया गया क्योंकि सभी सदस्य सरकार के होंगे। यह श्रीकृष्ण समिति के सुझाव के उलट है जिसने कहा था कि इसमें कार्यपालिका, न्यायिक और बाहरी उपक्रमों के साथ लोगों को भी शामिल करना चाहिए।

मसौदे में डीपीए के गठन के लिए कोई मियाद तय नहीं की गई है। यदि सोशल मीडिया मंचों को 'स्वैच्छिक' प्रमाणन की प्रक्रिया बताने पर मजबूर किया गया तो इससे अभिव्यक्ति की आजादी को नुकसान होगा और उनकी निजता को नुकसान होगा जो प्रमाणन करवाएंगे। यदि कोई व्यक्ति यह 'स्वैच्छिक' प्रमाणन नहीं कराता तो सरकारी एजेंसियां उसे निशाना बना सकती हैं। इससे प्रोफाइलिंग और डेटा उल्लंघन का खतरा भी बढ़ेगा। जो डेटा व्यक्तिगत नहीं है उसे सरकार को देने के प्रावधान का भी दुरुपयोग हो सकता है। गैर व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा बहुत व्यापक है। यहां तक कि ई-कॉमर्स बिक्री रुझान से भी जाति, धर्म, चिकित्सकीय स्थिति, यौनिकता, पठन की आदत जैसी निजी जानकारी जुटाई जा सकती है। सरकार की पहुंच और निर्बाध निगरानी क्षमता के चलते गैर व्यक्तिगत और व्यक्तिगत डेटा को मिलाया जा सकता है। उस आंकड़े से मतदाताओं को प्रभावित करने या धमकाने का काम किया जा सकता है। यह दुखद है कि देश का पहला निजता कानून इतनी कमियों वाला है। यह भी विडंबना ही है कि इसे न्यूनतम पारदर्शिता के बिना पारित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे गड़बड़ीयुक्त कानून बन सकता है। यदि विपक्ष बहस और संशोधन पर जोर नहीं देता तो ऐसा कानून बन सकता है जो आम जन का बचाव नहीं कर पाएगा।

अजय मोहंती

ढांचागत क्षेत्र में तरलता प्रवाह हो निर्बाध

आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए ढांचागत क्षेत्र काफी अहम है। मध्यस्थता पंचाटों के भुगतान संबंधी फैसलों पर प्रक्रियागत सुधार करने जरूरी हैं। बता रहे हैं **विनायक चटर्जी**

अक्सर ऐसा होता है कि मीडिया में उन खबरों को अधिक प्रमुखता नहीं दी जाती है जिनमें अनुकूल दीर्घकालिक प्रभाव डालने की क्षमता होती है। गत 20 नवंबर को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने ऐसे तरीके पर मुहर लगाई जो ढांचागत क्षेत्र के लिए कुछ राहत लेकर आएगा। यह एक ऐसा कदम है जिस पर इस क्षेत्र के बाहर शायद ही ध्यान दिया गया है।

सीसीईए ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) जैसी सरकारी इकाइयों के लिए मध्यस्थता विवादों में फंसी राशि का 75 फीसदी तक हिस्सा फौरन जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी है। इससे निजी क्षेत्र के साथ विवादों के चलते फंसी रकम में से 75 फीसदी तक राशि निकालने का रास्ता आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि यह सुविधा उस स्थिति में भी मिलेगी जब मध्यस्थता अधिकरण के फैसलों के खिलाफ सरकारी इकाइयों ने अपील कर रखी हो। भले ही नीति आयोग ने वर्ष 2016 में इस संदर्भ में निर्देश जारी किए थे लेकिन इस पर ठीक से अमल नहीं किया गया था। संबंधित सरकारी संस्थानों की तरफ से इस 75 फीसदी राशि मुक्त करने के पहले संभावित ब्याज को भी कवर करने के लिए बैंक गारंटी की मांग बड़ा अवरोध होती थी। सीसीईए के हालिया फैसले में सरकारी संस्थानों को कहा गया है कि वे विवादित रकम के कम-से-कम ब्याज वाले हिस्से के लिए गारंटी की मांग न रखें। निजी क्षेत्र में तरलता की भारी किल्लत होने से ऐसी गारंटी को भुना पाना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में तरलता बनाए रखने के लिए अधिक तरलता की जरूरत है।

यह उम्मीद की गई है कि भविष्य में प्रक्रिया को सरल बनाकर ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि बैंक गारंटी की जरूरत ही न रह जाए। इन दिनों ढांचागत क्षेत्र की कंपनियों को बैंक गारंटी मिलने में पेश आने वाली चुनौतियों को देखते हुए यह बेहद जरूरी है। बैंकों को गारंटी देने के लिए प्रोत्साहित करने और सरकारी इकाइयों के लिए बकाये के निपटारे के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से बैंकों को एक अलग बायर्स लाइन ऑफ क्रेडिट देने पर विचार करने का अनुरोध किया था जिसका इस्तेमाल सरकारी एजेंसियां मध्यस्थता निर्णयों के तहत वेंडरों का भुगतान करने के लिए कर सकती हैं। उस रकम का इस्तेमाल बैंकों को कर्ज लौटाने में किया जा सकता है।

सीसीईए का यह निर्णय अब नीति आयोग के महज एक निर्देश से अलग हटकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का फैसला होने जा रहा है जिसे सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। यह इस बात को स्वीकार करता है कि उत्पादों एवं सेवाओं की सबसे बड़ी खरीदार होने के नाते खुद सरकार ही तरलता संकट खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाती है। भुगतान में देरी से अक्सर दूरगामी प्रभावों का सिलसिला शुरू हो जाता है जिसका नतीजा निजी फर्मों के दिवालिया होने के रूप में सामने आता है क्योंकि ये फर्में काफी हद तक सरकारी ठेकों पर ही निर्भर होती हैं। अनुमानित तौर पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों पर बकाया है। मध्यस्थता विवादों में जीत के बाद वेंडरों एवं आपूर्तिकर्ताओं को यह रकम दी जानी है। इतना ही अहम यह है कि सीसीईए की बैठक में यह भी कहा गया कि सरकारी इकाइयों को मध्यस्थता अधिकरणों के निर्णयों के खिलाफ अपील करने के पहले सरकार के कानूनी अधिकारी (मसलन, अटॉर्नी जनरल या सोलिसिटर जनरल) की राय लेनी चाहिए। यह हारे हुए मामले को अदालत में ले जाने की सरकारी इकाई की यंत्रवत प्रतिक्रिया को सीधे तौर पर कम करेगा। उम्मीद है कि इस एक कदम से ही अदालतों में दाखिल की जाने वाली अपीलों में भारी कमी आएगी।

प्रसंगवश, मध्यस्थता अधिनियम समस्या की गंभीरता को मान्यता देता है। वर्ष 2015 में इस कानून में किए गए बदलाव मध्यस्थता निर्णयों को दी जाने वाली चुनौती में कमी लाने और ऐसे निर्णयों के तहत भुगतान की प्रक्रिया तेज करने के लिए लाए गए थे। हालांकि इस साल के शुरू में किए गए संशोधनों ने इस सुधार को 2015 के बाद के विवादों के लिए ही प्रभावी कर दिया। इन हालिया संशोधनों को उच्चतम न्यायालय ने गत 27 नवंबर को निरस्त कर दिया है जो ढांचागत क्षेत्र के लिए एक और राहत की बात है। मध्यस्थता पंचाटों के फैसले आना कहानी का एक हिस्सा है। नकद-प्रवाह की समस्या का दायरा आम तौर पर सरकार से समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने से जुड़ा है, यहां तक कि सामान्य बिलों के मामले में भी। ढांचागत क्षेत्र के तमाम विश्लेषक इसकी तसदीक करेंगे कि हरेक गुजरते महीने में निजी क्षेत्र की बैलेंस शीट पर बकाया भुगतान के दिनों की संख्या चिंताजनक दर से बढ़ती दिख रही है। इसका बड़ा कारण भुगतान को समय पर जारी करने की जवाबदेही का पूर्ण अभाव है। लिहाजा एक रसीद तैयार होने के साथ ही वह अफसरशाही की भूलभूलैया में एक से दूसरी मेज तक घूमती रहती है और कई महीनों तक पीछा करने के बाद वह रकम बैंक खाते में जमा हो पाती है। कारोबार से सरकार (बी-टू-जी) संपर्क की ऐसी व्यवस्था में तत्काल बदलाव लाने की जरूरत है।

सीआईआई ने सभी तरह की सरकारी खरीद इकाइयों के लिए बकाया भुगतान का एक पोर्टल बनाने का सुझाव कई बार दिया है। इस तरह के मोटे आंकड़े जीएसटी ढांचे में हरेक रसीद का विवरण दर्ज होने से पहले से ही उपलब्ध हैं। एक साधारण की प्रोग्रामिंग कर किसी एक निकाय के नाम पर जारी सभी रसीदों को एक साथ देखा जा सकता है। इससे उन रसीदों की भी शिनाख्त हो सकेगी जिन पर भुगतान बाकी है। अगर यह फौरन लागू होता है तो राजनीतिक आका भी समस्या की भयावहता देखकर हिल सकते हैं।

सरकार ने इसके बाद यह घोषणा की है कि केंद्र सरकार के विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों से भुगतान में देरी पर व्यय सचिव की तरफ से निगरानी रखी जाएगी और कैबिनेट सचिवालय के स्तर पर उसकी समीक्षा होगी। ऐसे सवाल उठाए गए हैं कि वाणिज्यिक बैंकों एवं एनबीएफसी के नदारद होने पर दीर्घावधि तरलता को ढांचागत क्षेत्र के लिए समर्पित विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के जरिये भेजा जाना चाहिए। ऐसे खुरदुरे उपाय सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच फंड के प्रवाह की बाधाएं दूर कर देते हैं। सरकार को इसे अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी राहत पैकेज में शामिल करना चाहिए।

(लेखक सलाहकार फर्म फीडबैक इन्फ्रा के चेयरमैन हैं)

घातक बीमारियों से निजात दिलाएगा एडीज का जीवाणु से संक्रमण

तकनीकी तंत्र

देवांग्शु दत्ता

मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों से जंग का एक रोचक तरीका यह है कि मच्छरों को परजीवी से संक्रमित करा दिया जाए। एडीज एजिप्टी प्रजाति के मच्छर में ऐसे विषाणु होते हैं जो डेंगू, जिका, पीत ज्वर और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के कारक बनते हैं। इस प्रजाति के मादा मच्छर जब इंसानों को काटते हैं और उनके रक्त में अपने विषाणु छोड़ देते हैं। ये विषाणु मच्छर की कोशिकाओं के भीतर पनपते रहते हैं। जब विषाणु-संक्रमित मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो फिर इन बीमारियों के विषाणु भी पहुंचा देता है।

डेंगू से हर साल 5-10 करोड़ लोग संक्रमित होते हैं जबकि लातिन अमेरिका में जिका महामारी का नवजात शिशुओं पर भयावह असर रहा है। ब्राजील एवं अफ्रीकी देशों में पीत ज्वर का प्रकोप है और चिकनगुनिया ने कई महाद्वीपों में महामारी फैलाई है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि वोल्बाचिया नाम का एक जीवाणु इन मच्छरों में विषाणु संक्रमण कर सकता है। यह जीवाणु एक परजीवी है जो कई रूपों में आता है। कीटों की करीब 60 फीसदी प्रजातियों में यह स्वाभाविक तौर पर मौजूद होता है। कुछ कृमि प्रजाति नेमाटोड्स में भी वोल्बाचिया पाया जाता है। लेकिन एडीज मच्छर इस परजीवी का सामान्य वाहक नहीं है।

यह जीवाणु दो तरह से विषाणु संक्रमण को फैलाता है। इससे मच्छर से प्रतिरोधकता देने वाली प्रणाली मजबूत होती है जिसकी वजह से विषाणु इसे संक्रमित नहीं कर पाता है। यह कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रमुख अणुओं के लिए विषाणुओं से प्रतिस्पर्द्धा भी करता है। विषाणुओं को अपना वजूद बनाए रखने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है और वोल्बाचिया कोलेस्ट्रॉल के सेवन में काफी कारगर है। लिहाजा यह मच्छर को संक्रमित कर पाने वाले किसी भी विषाणु को पोषण से वंचित कर देता है।

नेमाटोड्स में मौजूद वोल्बाचिया के कुछ रूप खतरनाक होते हैं। वे सूजन पैदा कर सकते हैं जो आगे चलकर फाइलेरिया जैसी बीमारी में भी तब्दील हो सकता है। लेकिन मच्छर-विरोधी प्रयोगों में लगे शोधकर्ताओं ने वोल्बाचिया के जिस रूप का इस्तेमाल किया है वह इंसानों एवं बड़े जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस वजह से इस जीवाणु को मच्छर में संक्रमित कराना सुरक्षित एवं पर्यावरण के लिहाज से संपोषणीय है। मेलबर्न एवं ग्लासगो स्थित विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और मलेशिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ने विश्व मच्छर कार्यक्रम (डब्ल्यूएमपी) के साथ मिलकर एडीज मच्छरों में वोल्बाचिया को पहुंचाने के प्रयोग किए हैं। वर्ष 2011 में मेलबर्न की मोनाश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्कॉट ओनील की अगुआई में शोधकर्ताओं ने एडीज मच्छरों के अंडों में वोल्बाचिया को इंजेक्ट करना शुरू किया था।

उन्होंने प्राकृतिक तौर पर फल मक्षिकाओं (फ्रूट फ्लाई) में मौजूद जीवाणु से वोल्बाचिया को लिया था। एडीज के अंडों को सेने के बाद वोल्बाचिया-संक्रमित एडीज को क्वींसलैंड के कुछ इलाकों में जंगली एडीज मच्छरों के साथ निषेचन के लिए छोड़ दिया गया। समय बीतने पर यह पता चला कि परीक्षण के लिए चुने गए इलाकों में एडीज-जनित बीमारियों के मामले नगण्य थे जबकि बाकी इलाकों में उनकी संख्या यथावत थी।

वोल्बाचिया-संक्रमित नर मच्छर का एक असंक्रमित मादा मच्छर से मिलन होने पर निकले अंडे निर्जीव थे। लेकिन वोल्बाचिया-संक्रमित मादा मच्छर असंक्रमित नरों के साथ मिलकर अंडे दे सकती है जिससे निकलने वाले नवजात मच्छर में वोल्बाचिया मौजूद होंगे। ये जीवाणु-वाहक मच्छर आने वाली कई पीढ़ियों में इसे फैलाते जाएंगे। इसका नतीजा यह होगा कि एक समय बाद महामारी फैलाने वाली विषाणु-जनित बीमारियों के संक्रमण की दर नीचे आ जाएगी।

यह तरीका लंबी अवधि में अधिक कारगर साबित हो सकता है और इससे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर भी कोई प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना नहीं है। यह लागत के लिहाज से भी किफायती होगा क्योंकि जीवाणु पीढ़ी-दर-पीढ़ी खुद ही अपना प्रसार करता जाता है।

शोधकर्ताओं का दावा है कि इस जीवाणु-संक्रमण के बाद नॉर्दर्न क्वींसलैंड इलाके में एडीज-जनित बीमारियां लगभग नदारद हो चुकी हैं। डब्ल्यूएमपी ने 12 देशों में परियोजनाएं चलाई हैं जिनमें 40 लाख आबादी वाले इलाकों में परीक्षण चल रहे हैं। शुरुआती अध्ययनों में वोल्बाचिया का एक रूप डब्ल्यूमेल शामिल था। लेकिन डब्ल्यूमेल के साथ मुश्किल यह है कि यह अधिक तापमान सहन नहीं कर सकता है। दूसरे शोध दल ने यह पाया कि वोल्बाचिया की एक दूसरी किस्म उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भी बेहतर परिणाम दे सकती है। इस दल के अगुआ स्टीवन सिन्किंस हैं जो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में जैवविज्ञानी हैं। सिन्किंस ने कुआलालंपुर के छह चुनिंदा इलाकों में डब्ल्यूएल्बबी नामक जीवाणु-प्रजाति का इस्तेमाल किया जो अधिक तापमान में भी मच्छरों को संक्रमित कर सकता है। 'करंट बायोलॉजी' में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, डब्ल्यूएल्बबी किस्म वाला जीवाणु 36 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में भी सक्रिय रह सकता है।

डब्ल्यूएमपी का दावा है कि वोल्बाचिया जीवाणु के इस्तेमाल को लेकर तीन स्वतंत्र जोखिम आकलन किए गए हैं। इनमें नाममात्र का जोखिम पाया गया यानी वोल्बाचिया जीवाणु इंसानों, जानवरों एवं पर्यावरण तीनों के लिए सुरक्षित है।

एडीज मच्छरों पर काबू पाने के दूसरे जैविक तरीकों में अधिक जोखिम हैं। बड़ी आबादी वाले इलाके में आनुवांशिक रूप से संवर्द्धित मच्छरों का इस्तेमाल कर उन्हें प्रजनन से रोकने में बहुत लंबा वक्त लगता है। मच्छर की एक स्थानीय आबादी को पूरी तरह खत्म कर देने के नकारात्मक पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। आखिर कीट-पतंगे भी खाद्य शृंखला का एक अहम हिस्सा हैं। ऐसे में डब्ल्यूएमपी को वोल्बाचिया जीवाणु को लेकर अपने प्रयोगों का दायरा बढ़ाने की जरूरत है।

कानाफूसी

अध्यक्ष पद की लड़ाई

क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अचानक सक्रियता का राज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में छिपा है ? चौहान ने हाल ही में प्रदेश में व्याप्त यूरिया संकट के खिलाफ कुछ किसानों के साथ गिरफ्तारी दी। इसके बाद वह एक बलात्कार पीड़ित के मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए धरने पर बैठे। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा करके वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष यह जताने का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पार्टी को एक तेज तर्रार अध्यक्ष की आवश्यकता है। मौजूदा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह उतने सक्रिय नजर नहीं आते हैं। फिलहाल तो प्रदेश भाजपा दो धड़ों में बंटी नजर आती है। एक धड़ा शिवराज सिंह चौहान को पसंद करता है तो दूसरा राकेश सिंह के साथ है।

कम हो वजन

संसद में मंगलवार को संसद सदस्यों के लिए एक व्याख्यान का आयोजन किया गया जो वजन कम करने और मधुमेह से संबंधित था। सांसदों को जारी एक परामर्श में कहा गया कि यह आयोजन फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया। इस मौके पर डॉ. जेवी दीक्षित ने सांसदों को संबोधित किया और बिना किसी खास प्रयास के वजन कम करने के तरीकों और उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने मोटापे, मधुमेह, रक्त अल्पता और माइग्रेन के बारे में भी बताया। व्याख्यान में शामिल भाजपा के सीआर पाटिल तथा कुछ सदस्यों ने कहा कि एक दिन में दो बार भोजन करने की दीक्षित की सलाह से उन्हें फायदा हुआ है। दीक्षित का डाइट प्लान महाराष्ट्र में काफी लोकप्रिय है लेकिन विशेषज्ञ इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। गत वर्ष इस आयोजन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने कहा था कि महाराष्ट्र में होने वाली शादियों में रात्रिभोज में उन लोगों के लिए भी समय निर्धारित होता है जो दीक्षित की योजना के अनुसार भोजन करते हैं।

आपका पक्ष

विधेयक बेहतर तो विरोध क्यों

देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा पेश नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया है। देश के कई हिस्सों में इस विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने उनको भरोसे में लिए बगैर लोकसभा से विधेयक पारित करा दिया है। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि सत्तारूढ़ भाजपा इस विधेयक के माध्यम से हिंदू वोट बैंक को सुनिश्चित करना चाहती है। विपक्षी पार्टियां भी धर्म के आधार पर नागरिकता देने को लेकर विरोध कर रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के संघीय आयोग का कहना है कि यह विधेयक गलत दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। देश में विधेयक को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी धर्मों को एकसमान अधिकार देता है। लेकिन विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगनिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थी को नागरिकता देने की व्यवस्था रखी गई है जो विवाद का कारण है। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 के मुताबिक कानून के आगे सभी को बराबरी का अधिकार प्राप्त है जबकि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य अपने किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है जिस वजह से यह विधेयक की प्रमाणिकता को लेकर लोगों के मन में कई सवाल पैदा कर रहा है। मंत्रिमंडल के मंत्री शपथ समारोह में भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। इसलिए सरकार को विधेयक में मौजूद कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा आज देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी आदि समस्याएं हैं जिसे प्राथमिकता देकर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक राज्य सभा में पेश किया गया -पीटीआई

अनेकता में एकता पर सवाल

नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद क्या भारत की अनेकता में एकता पर सवाल नहीं उठेगा। इस सवाल का जवाब खोजना मुश्किल नहीं है। बस जिन लोगों पर इसका असर पड़ेगा उनकी जगह पर स्वयं को रख कर देखना होगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद यह कानून का रूप लेगा तब भारत में जो परिवर्तन होगा उसे तो हम समझ जाएंगे लेकिन भारत के बाहर अर्थात बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा इसे भी समझना जरूरी होगा। इस विधेयक को अपनाने के साथ कहीं हम जिन्ना की 'टू नेशन थ्योरी' को तो नहीं अपना रहे हैं। इस पर भी विचार करना जरूरी है क्योंकि इसका परिणाम अंत में आम आदमी को ही भुगतना पड़ेगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद एक बहुत बड़ी आबादी की अदला-बदली होगी। उम्मीद है कि यह सब सोच कर ही सरकार ने इस विधेयक को लाने का फैसला किया होगा।

भूपेंद्र सिंह रंगा, पानीपत

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

प्याज की महंगाई किसान के काम न आई

बाढ़ में प्याज की फसल और पुराना स्टॉक बरबाद होने से किसानों को नहीं मिल पा रहा फायदा

दिलीप कुमार झा
लासलगांव, 11 दिसंबर

महाराष्ट्र के प्याज-उत्पादक जिले नाशिक में निफाड तालुका के किसान रघुनाथ सावंत इन दिनों काफी परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण यह है कि देश भर में जिस प्याज के खुदरा भाव 130-140 रुपये प्रति किलो तक जा पहुंचे हैं, उस प्याज को उपजाने के बावजूद उन्हें इस तेजी का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। वह इस परेशानी का सामना करने वाले अकेले किसान नहीं हैं। उनकी तरह सैकड़ों अन्य प्याज उत्पादकों को भी यही बात परेशान कर रही है।

सावंत अपनी बेबसी बयां करते हुए कहते हैं, 'मैंने 55 साल की अपनी जिंदगी में प्याज के इतने ऊंचे भाव नहीं देखे हैं। लेकिन इस आसमान छूती कीमत का किसानों के लिए कोई मतलब नहीं रह गया है। सितंबर-अक्टूबर में हुई भारी बारिश ने गोदाम में रखे प्याज को काफी नुकसान पहुंचाया था। पिछले साल उपजाए गए प्याज को अच्छे भाव पर बेचने की मंशा से किसानों ने गोदामों में रखा था लेकिन ज्यादा बारिश से आई बाढ़ ने सब बरबाद कर दिया।'

वह बताते हैं कि बाढ़ की वजह से इस खरीफ मौसम में प्याज की फसल को भी दो बार काफी नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति में किसानों को तीसरी बार प्याज के बीज डालने पड़े थे। इससे न केवल प्याज के उत्पादक किसानों की लागत काफी बढ़ गई बल्कि फसल तैयार होने में छह हफ्ते की देरी भी हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि नई फसल की आवक शुरू होने तक प्याज के भाव 50 फीसदी तक चढ़ चुके थे।

लासलगांव में खराब प्याज को फेंक दिया गया -फोटो कमलेश पेडणेकर

सावंत की ही तरह लासलगांव में प्याज की खेती करने वाले अर्जुन हिंगोले की भी कुछ ऐसी ही राय है। तीन एकड़ जमीन में खेती करने वाले हिंगोले कहते हैं, 'प्याज उगाने वाले किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। पहले तो उनका पिछली उपज का माल बाढ़ के पानी ने बरबाद कर दिया और फिर इस बार प्याज की उपज भी कम हो गई।'

देश भर में प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। खुदरा बाजार में प्याज 130-140 रुपये प्रति किलो के स्तर तक जा पहुंचा है। वहीं थोक बाजार में भी यह 70-80 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहा है। ऐसे में प्याज की खेती करने वाले किसानों ने ऊंचे भाव का फायदा उठाने के लिए अपनी फसल तैयार नहीं होने पर भी प्याज को खेतों से निकालना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के प्याज उत्पादक किसान अधपके प्याज को भी खेतों से निकाल रहे हैं। लेकिन मिट्टी में काफी नमी होने से प्याज पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं जिससे पैदावार 40 फीसदी तक गिर गई।

जानकारों का अनुमान है कि इस खरीफ मौसम में प्याज की 30 फीसदी फसल बरबाद होने से अकेले लासलगांव में ही इसकी उपज करीब 20 लाख टन कम हो गई है। अगर देश भर में इस नुकसान का अनुमान लगाया जाए तो इस साल करीब 70 लाख टन प्याज कम उपजेगा। इसकी भरपाई के लिए गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल जैसे गैर-परंपरागत प्याज उत्पादक राज्यों में प्याज का रकबा बढ़ाने की जरूरत होगी।

किसानों को अब यह बात परेशान कर रही है कि जब उनके खेतों से प्याज निकलने लगे हैं तो प्याज के दामों में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में भी यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है। एपीएमसी लासलगांव के चेयरमैन सुवर्ण जगताप कहते हैं, 'प्याज की कीमतों के इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है क्योंकि मौसमी लाल प्याज की स्थानीय आवक बढ़ गई है। किसान भी ऊंचे भाव का लाभ उठाने के लिए अपरिपक्व प्याज को खेतों से निकाल रहे हैं। इस वजह से पिछले दो दिनों में ही प्याज के भाव 42 फीसदी तक गिरकर लासलगांव की थोक मंडी में 41 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं। अगले दो हफ्तों में इस मंडी में प्याज की कीमत 20-25 रुपये प्रति किलो तक आ जाने की संभावना है।'

एपीएमसी लासलगांव के सचिव नरेंद्र वाधवाने कहते हैं कि किसी भी जिंस उत्पाद के बढ़े हुए भाव फौरन खुदरा स्तर पर नजर आने लगते हैं जबकि कीमत होने का असर आने में हफ्ता भर लग जाता है। वाधवाने कहते हैं, 'ऐसी स्थिति में प्याज के थोक मंडी में प्याज के भाव गिरने का असर बाजार तक आने में 7-10 दिन लग जाएंगे।'

वहीं इस संस्था के पूर्व चेयरमैन जयदत्त होल्कर ने सरकार से प्याज के भंडारण पर लगी सीमा हटाने की मांग की है।

एक रोचक पहलू यह है कि हर तीन साल पर प्याज के भाव बढ़ जाते हैं। इस कीमत को देखते हुए किसान अधिक रकबे में प्याज उगाते हैं जिससे अगले दो साल तक इसके भाव नीचे रहते हैं। इस बीच किसानों के लिए राहत की बात यह है कि अब ठंडी हवाएं बहने लगी हैं और मिट्टी की कमी भी कम होने लगी है। ऐसी जलवायु प्याज की उपज बढ़ाने में मददगार होती है।

लगातार दो सालों से नहीं बढ़ाए गए गन्ने के दाम

गन्ना कीमतों में इजाफे को लेकर उप्र के किसानों का विरोध प्रदर्शन

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 11 दिसंबर

पेराई सत्र 2019-20 में गन्ने के दामों में इजाफा नहीं किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश में आज किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के समर्थन से लखनऊ सहित राज्य के राजमार्ग अवरुद्ध कर दिए।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है जिसमें दावा किया गया है कि उनके शासन काल में उर्वरक के दाम दोगुने हो चुके हैं। इसके अलावा बिजली और कृषि की श्रम लागत में भी भारी इजाफा हुआ है। उन्होंने पिछले चीनी सत्र के बकाया भुगतान पर भी ध्यान दिलाया है।

शनिवार को राज्य सरकार ने कहा था कि वह इस नकदी फसल की सामान्य किस्म के लिए राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) को 315 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर बरकरार रखेगी। गन्ने की शुरुआती और अनुपयुक्त किस्मों के लिए भी गन्ने का एसएपी प्रति क्विंटल क्रमश: 325 रुपये और 310 रुपये रखा गया है। यह लगातार दूसरा ऐसा वर्ष है जब आदित्यनाथ सरकार ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि नहीं की। राज्य सरकार ने अपने पहले वर्ष में 2017-18 सत्र के दौरान एसएपी में प्रति क्विंटल (सामान्य किस्म) 10 प्रतिशत तक का इजाफा किया था।

बीकेयू ने महंगाई और खेती से संबंधित वस्तुओं की लागत बढ़ने का हवाला देते हुए गन्ने के दाम प्रति क्विंटल 450 रुपये करने की मांग की है। बीकेयू अध्यक्ष (उत्तर प्रदेश) दीवान चंद्र चौधरी ने कहा कि गन्ने के दाम बढ़ाकर प्रति क्विंटल 450 रुपये करने और गन्ना बकाये का ब्याज समेत भुगतान करने के संबंध में अब हमने सरकार को 21 दिसंबर तक का समय दिया है। हमने उनसे पराली जलाने समेत पर्यावरण के नाम पर किसानों का उत्पीड़न रोकने के लिए भी कहा है।

- सरकार से खफा किसानों ने लखनऊ सहित राज्य के राजमार्ग किए अवरुद्ध
- गन्ना किसानों को राहत के लिए प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
- राज्य सरकार ने 2017-18 सत्र के दौरान एसएपी में प्रति क्विंटल (सामान्य किस्म) किया था 10 प्रतिशत तक का इजाफा

बीकेयू ने चेतावनी दी है कि वह लंबित मुद्दों पर 21 दिसंबर को एक और जोरदार राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। सरकार ने बीकेयू द्वारा सामान्य जन-जीवन या यातायात बाधित करने का प्रयास विफल करने के लिए बुधवार को व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने आज एक समाचार चैनल को बताया कि सरकार गन्ना बकाये का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 11	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,750.0	-2.4	1,905.7	-3.1
Copper	6,055.0	5.0	6,437.0	4.6
Nickel	13,070.0	-28.7	14,257.5	-21.7
Lead	1,893.0	-9.9	2,188.0	6.7
Tin	17,320.0	-0.5	18,280.6	-0.7
Zinc	2,222.0	-6.0	2,597.4	-1.0
Gold ($/ounce)	1,466.0*	-2.1	1,652.7	0.7
Silver ($/ounce)	16.7*	-8.1	19.0	-6.5
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	65.1*	5.8	64.8	4.9
Natural Gas ($/mmBtu)	2.3*	-10.6	2.3	-11.3
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	182.3	9.7	300.8	6.1
Maize	182.2*	1.8	322.4	12.9
Sugar	352.7*	13.8	484.5	0.3
Palm oil	712.5	33.2	1,117.3	28.5
Rubber	1,622.7*	6.2	1,863.4	-4.6
Coffee Robusta	1,458.0*	10.4	1,898.6	-7.4
Cotton	1,448.7	10.7	1,583.5	-1.2

* As on Dec 11, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 70.8& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	27.7	12876
Oil and Oilseeds	377.3	76774
Spices	0.4	14
Metal(Dec 10)		
Metal- non ferrous	5959.6	59295
Metal- precious	7138.6	537
Oil and gas(Dec 10)		
Gas	2301.9	44675
Oil	13186.8	2564

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	143.3	106554
Grains	159.9	102415
Oil and Oilseeds	661.3	498455
Others	127.7	67960
Pulses	158.3	58665
Spices	64.3	32213

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Natural Gas (Dec 26)	160.8	2.4
Nickel (Dec 31)	991.5	1.2
Lead (Dec 31)	153.3	0.4
Lead Mini (Dec 31)	153.2	0.4
Kapas (Apr 30)	1084.5	0.1
Gold Guinea (Dec 31)	30435.0	0.1
Losers (* % Change)		
Zinc (Dec 31)	181.6	-0.6
Zinc Mini (Dec 31)	181.9	-0.6
Aluminium Mini (Dec 31)	132.3	-0.2
Aluminium (Dec 31)	132.3	-0.2
Gold Mini (Jan 03)	37604.0	-0.1
Copper (Dec 31)	439.2	-0.1

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6008.0	4.0
GuarGum 5T-Jodhpur (Dec 20)	7168.0	1.9
Guar Seed 10 (Dec 20)	3948.0	1.5
Coriander-Kota (Dec 20)	6987.0	1.2
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	4194.0	1.1
Soyabean Indore (Dec 20)	4162.0	0.3
Mustard Seed Rape Oil (Dec 20)	4400.0	0.3
Losers (* % Change)		
CottonSeed Oil-Akola (Dec 20)	1998.0	-1.2
Chana-Bikaner (Dec 20)	4329.0	-1.0
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	852.2	-0.7
Jeera Unjha (Dec 20)	16450.0	-0.4
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1080.5	-0.3

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cardamom Vandanmedu (Dec 13)	3051.1	3.3
Gold Petal-Mumbai (Dec 31)	3850.0	2.0
Kapas Surendranagar (Feb 28)	1043.0	2.0
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19070.0	1.4
Nickel Mumbai (Dec 31)	991.5	1.2
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	43535.0	0.8
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1306.1	-7.7
Aluminium Mum (Dec 31)	132.3	-4.4
Alumini-Mumbai (Dec 31)	132.3	-4.4
Copper Mum (Dec 31)	439.2	-3.4
Lead Min Mumbai (Dec 31)	153.2	-1.3
Lead Mum (Dec 31)	153.3	-1.3

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6008.0	0.7
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	734.7	0.5
Jeera Unjha (Dec 20)	16450.0	0.4
29 mm Cotton-Rajkot (Dec 20)	18700.0	0.4
Barley Jaipur (Dec 20)	2117.5	0.4
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3205.0	0.2
Maize-Sangli (Dec 20)	2026.0	0.1
Discount over spot price (In %)		
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7168.0	-1.0
Coriander-Kota (Dec 20)	6987.0	-0.8
Moong-Merta City (Dec 20)	6658.0	-0.3
Soy Bean Indore (Dec 20)	4162.0	-0.3

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	..............Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	100.....................(100)
Aluminium ingots /kg	135.....................(135)
Brass sheet cutting /kg	317.....................(316)
Brass utensil scraps/kg	300.....................(299)
Copper heavy scrap /kg	420.....................(419)
Copper utensil scraps/kg	397.....................(395)
Copper wire bar /kg	456.....................(453)
Lead ingots /kg	155.....................(154)
Nickel Cathodes /kg	1010.....................(990)
Tin slabs /kg	1295..................(1295)
Zinc slabs /kg	184.....................(184)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	..............Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10742.................(10742)
DCH - 32 /Qtl	11473.................(11473)
Jaydhar /Qtl	10067.................(10067)
Shankar- 6 /Qtl	11276.................(11276)

Source:Cotton Association of India

Oil	..............Mumbai
Castor FSG /10kg	892.....................(892)
Castor Comm /10kg	882.....................(882)
Ricebran oil/10kg	760.....................(760)
Groundnut oil /10kg	1050..................(1050)
Linseed oil /10kg	805.....................(845)
Karanji /10kg	780.....................(780)
Palm oil /10kg	807.....................(810)
Sunflower exp ref /10kg	850.....................(865)
Sunflower oil exp /10kg	810.....................(815)
Soyabean ref / 10kg	855.....................(855)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	..............Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3292-3572 ....(3292-3572)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	....
NYSE Crude	58.9..................(59.24)
Brent Crude (UK)	65.11 ....(65.29)
Brent Crude (WTI)	59.24................(59.24)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu	2.27 ....(2.26)
Furnace/ 180 Cst &/bbl	272 ....(267.31)
Naptha spot /Rs/MT	45170.................(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150.................(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950.................(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	..............Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	37641.................(37615)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	37792.................(37766)
Silver.999/ kg	43260.................(43275)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18667.45	18630.60
Alumini-Mumbai (M)	1 K	138.45	138.45
Bajra-Delhi (N)	1 Q	1925.00	1950.00
Barley Jaipur (N)	1 Q	2114.15	2109.65
Brass-Jamnagar (M)	1 K	313.00	313.00
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3017.00	3033.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4220.85	4231.65
Castor Seed-Kadi (N)	X	4200.00	4200.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4260.85	4250.00
Chana Delhi (N)	1 Q	4450.00	4450.00
Chana-Akola (N)	X	4362.50	4350.00
Coriander-Gondal (N)	X	6611.00	6800.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6903.35	6921.25
Coriander-Kota (N)	1 Q	6987.15	7042.35
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2122.50	2098.20
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2055.90	2026.65
Cotton-Kadi (N)	1 B	18596.75	18513.10
CPO-Kandla (M)	10 K	717.20	717.20
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	732.35	731.25
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	880.80	877.45
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1537.60	1531.80
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3450.50	3436.25
Gold Ahm (M)	10 G	37590.00	37590.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30193.00	30193.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3773.00	3773.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7200.00	7237.50
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	3920.00	3926.50
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3938.00	3850.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1070.10	1100.90
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	93.40	93.55
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16950.00	16700.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16407.15	16387.50
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1030.05	1016.20
Kapas-Rajkot (N)	X	1026.20	1022.05
Lead Mum (M)	1 K	155.20	155.20
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	1980.00	1991.25
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2280.15	2292.65
Maize-Erode (N)	X	2034.10	2045.40
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2200.00	2200.00
Maize-Sangli (N)	X	2022.50	2023.35
Moong-Merta City (N)	1 Q	6647.20	6680.55
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4643.00	4623.70
Nickel Mumbai (M)	1 K	979.70	979.70
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3194.00	3187.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3200.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	351.00	353.00
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35100.00	35360.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	812.00	813.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2045.30	2036.95
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	791.25	791.50
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	857.70	852.15
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	852.05	853.00
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	870.00	868.75
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13200.00	13200.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13150.00	13200.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	43201.00	43201.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4171.00	4174.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4045.00	4141.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4229.40	4242.00
Soy Bean-Akola (N)	X	4201.00	4206.00
Soymeal Indore (N)	1 T	33869.00	33889.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	856.40	851.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	27720.00	27900.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	28800.00	28700.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	25820.00	25800.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3245.00	3245.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3351.15	3331.20
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3296.65	3293.75
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3457.15	3457.15
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3265.00	3250.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3130.85	3132.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	5864.60	5966.65
Wheat Delhi (N)	1 Q	2253.15	2250.00
Wheat Kota (N)	1 Q	2127.30	2126.20
Wheat New Indore (N)	1 Q	2195.00	2200.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2085.00	2082.50
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2200.00	2190.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	5100.00	5100.00
Zinc Mumbai (M)	1 K	182.35	182.35

* as on Dec 10, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (बुधवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19140, 19200, 19020, 19070	1156	224	8733
Jan 31	19300, 19350, 19180, 19220	1105	163	3163
Feb 28	19400, 19400, 19400, 19400	30	5	302
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	2006, 2027, 1990, 1998	10230	567	19700
Jan 20	2027, 2038, 1997, 2001	46800	2966	53970
Feb 20	2047, 2060, 2021, 2027	5740	530	26320
Mar 20	2059, 2087, 2043, 2055	510	49	2520
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1088, 1093.5, 1082.5, 1084.5	348	72	644
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1084, 1085.5, 1078, 1080.5	731	359	4034
Grains				
Barley Jaipur NCDEX(1 Q)				
Apr 20	1708.5, 1709, 1708.5, 1709	40	2	930
May 20	1715, 1715, 1715, 1715	30	3	900
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	3888, 3960, 3876, 3948	5735	679	13635
Jan 20	3944, 4032, 3932, 4000	33050	3783	78645
Feb 20	3986, 4072, 3986, 4046	1370	180	3650
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4140, 4208, 4128, 4194	4175	465	19360
Jan 20	4180, 4238, 4162, 4226	6550	832	26420
Feb 20	4156, 4200, 4156, 4188	175	10	3810
Mar 20	4170, 4238, 4160, 4226	255	28	4020
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	728.1, 731, 720.6, 724.2	27140	1711	34920
Jan 31	727.5, 729.1, 718.4, 723.6	17380	1165	37060
Feb 28	724, 725, 715.4, 721	2940	228	4470
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1278, 1314.9, 1278, 1306.1	236.16	553	276.48
Jan 31	1308, 1327, 1308, 1317.6	20.16	47	47.52
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4380, 4404, 4380, 4400	6540	360	8190
Jan 20	4412, 4432, 4409, 4418	5700	500	13510
Apr 20	4324, 4325, 4320, 4320	70	5	1670
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	855, 858.8, 851.4, 852.2	7110	694	15310
Jan 20	855, 859.8, 851, 854	19015	2148	51820
Feb 20	848, 857, 847.8, 851.2	1300	174	18835
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4146, 4194, 4128, 4162	15575	1698	22955
Jan 20	4162, 4226, 4162, 4198	43725	4536	175165
Feb 20	4200, 4256, 4198, 4226	13185	1495	104650
Mar 20	4230, 4282, 4230, 4250	4385	573	31425
Apr 20	4284, 4300, 4270, 4272	660	83	1065
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	7035, 7200, 7035, 7168	4235	417	4035
Jan 20	7117, 7310, 7093, 7265	12605	1770	61435
Feb 20	7248, 7405, 7248, 7375	885	127	2380
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4382, 4390, 4325, 4329	7950	578	10080
Jan 20	4410, 4419, 4328, 4338	27320	2035	44980
Mar 20	4335, 4335, 4285, 4294	900	76	2950
Apr 20	4345, 4345, 4300, 4300	100	9	560
May 20	4359, 4359, 4359, 4359	10	1	20
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Dec 13	3051.1, 3051.1, 3051.1, 3051.1	0.1	1	0.3
Jan 15	3120, 3120, 3061.3, 3099.3	0.8	8	11.8
Feb 14	2994.9, 2995, 2994.9, 2994.9	0.3	2	1.5
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6939, 7027, 6902, 6987	500	45	4750
Jan 20	6725, 6760, 6678, 6722	1010	92	7360
Apr 20	7106, 7139, 7075, 7112	310	30	3210
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Dec 20	16450, 16450, 16425, 16450	93	7	363
Jan 20	15830, 15900, 15770, 15810	594	186	2430
Mar 20	15805, 15875, 15640, 15640	33	11	168
Apr 20	15600, 15650, 15600, 15650	9	3	27
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	5800, 6008, 5800, 6008	1860	272	4785
Mar 20	5926, 6178, 5926, 6178	3650	587	6885
Apr 20	6010, 6184, 6010, 6184	1100	171	2230

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	132.4, 132.8, 132.1, 132.3	6115	983	7430
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	132.5, 132.85, 132.1, 132.3	2605	2201	3006
Jan 31	132.9, 133.3, 132.75, 132.9	371	247	671
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	438.25, 439.8, 437.5, 439.15	30257.5	10070	12847.5
Jan 31	443, 444, 442, 443.5	597.5	236	1222.5
Feb 28	447, 447, 447, 447	2.5	1	30
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.6, 153.35, 152.5, 153.25	17120	2912	4570
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	152.7, 153.35, 152.5, 153.2	6634	5372	2202
Jan 31	152.5, 152.6, 152.1, 152.4	287	260	713
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	976, 998, 961, 991.5	29994	17805	1945.5
Jan 31	972, 991.3, 958.2, 986	807	487	280.5
Feb 28	960, 960, 960, 960	1.5	1	-
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	183.35, 183.35, 181.35, 181.6	42575	6997	14600
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	183, 183.25, 181.75, 181.9	15649	11615	5376
Jan 31	181.8, 181.95, 180, 180.35	2589	1667	4396

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Feb 28	182.4, 182.4, 182.4, 182.4	1	1	5
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37677, 37700, 37534, 37571	10.37	8898	16
Apr 03	37615, 37771, 37587, 37658	0.48	399	2.26
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30481, 30485, 30391, 30435	0	327	0
Jan 31	30409, 30474, 30372, 30382	0	56	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37604, 37728, 37550, 37604	1.24	10198	0.81
Feb 05	37610, 37719, 37553, 37602	0.24	1968	0.33
Mar 05	37633, 37726, 37525, 37620	0	20	0
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3852, 3858, 3847, 3850	0	928	0.01
Jan 31	3829, 3838, 3822, 3823	0	296	0
Feb 28	3830, 3830, 3820, 3828	0	10	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	43485, 43700, 43410, 43507	407.04	11173	411.18
May 05	43906, 44150, 43906, 44025	1.71	54	6.09
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	43530, 43720, 43451, 43535	36.91	25081	35.48
Apr 30	44053, 44235, 43969, 44059	1.16	933	1.57
Jun 30	44465, 44590, 44465, 44528	0	2	0.01
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	43522, 43724, 43435, 43528	125.26	19067	61.44
Apr 30	44035, 44220, 44000, 44040	1.37	265	1.36

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	157.8, 162.7, 156.3, 160.8	134561mb	59603	30879mb
Jan 28	159, 162.9, 158.8, 161.4	8356mb	4787	10923mb
Feb 25	157.6, 160.3, 157.1, 159.4	1016mb	751	2874mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4191, 4214, 4152, 4195	24851bl	123638	1901bl
Jan 17	4192, 4217, 4158, 4198	814bl	5860	262bl
Feb 19	4170, 4215, 4170, 4192	0bl	3	0bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4195, 4213, 4151, 4196	5870bl	232348	401bl

सायं सत्र (मंगलवार)

कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19140, 19200, 19020, 19070	1156	224	8733
Jan 31	19300, 19350, 19180, 19220	1105	163	3163
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1088, 1093.5, 1082.5, 1084.5	348	72	644
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1088, 1093.5, 1083, 1086	1324	638	3919
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	728.1, 731, 720.6, 724.2	27140	1711	34920
Jan 31	727.5, 729.1, 718.4, 723.6	17380	1165	37060
Feb 28	724, 725, 715.4, 721	2940	228	4470
Mentha Oil MCX(1 K)				
Jan 31	1308, 1327, 1308, 1317.6	20.16	47	47.52
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	869.4, 869.4, 856.4, 856.8	11275	1136	15560
Jan 20	865, 865.4, 855.2, 856	26495	2951	48920
Feb 20	862, 862, 850.8, 852	4505	428	18830
Mar 20	845.2, 848.8, 845.2, 848.6	55	8	60
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Dec 13	3051.1, 3051.1, 3051.1, 3051.1	0.1	1	0.3
Jan 15	3120, 3120, 3061.3, 3099.3	0.8	8	11.8
Feb 14	2994.9, 2995, 2994.9, 2994.9	0.3	2	1.5

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	132.4, 132.8, 132.1, 132.3	6115	983	7430
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	132.5, 132.85, 132.1, 132.3	2605	2201	3006
Jan 31	132.9, 133.3, 132.75, 132.9	371	247	671
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	438.25, 439.8, 437.5, 439.15	30257.5	10070	12847.5
Jan 31	443, 444, 442, 443.5	597.5	236	1222.5

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Feb 28	447, 447, 447, 447	2.5	1	30
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	152.6, 153.35, 152.5, 153.25	17120	2912	4570
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	152.7, 153.35, 152.5, 153.2	6634	5372	2202
Jan 31	152.5, 152.6, 152.1, 152.4	287	260	713
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	976, 998, 961, 991.5	29994	17805	1945.5
Jan 31	972, 991.3, 958.2, 986	807	487	280.5
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	183.35, 183.35, 181.35, 181.6	42575	6997	14600
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	183, 183.25, 181.75, 181.9	15649	11615	5376
Jan 31	181.8, 181.95, 180, 180.35	2589	1667	4396
Feb 28	182.4, 182.4, 182.4, 182.4	1	1	5
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37677, 37700, 37534, 37571	10.37	8898	16
Apr 03	37615, 37771, 37587, 37658	0.48	399	2.26
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30481, 30485, 30391, 30435	0	327	0
Jan 31	30409, 30474, 30372, 30382	0	56	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37604, 37728, 37550, 37604	1.24	10198	0.81
Feb 05	37610, 37719, 37553, 37602	0.24	1968	0.33
Mar 05	37633, 37726, 37525, 37620	0	20	0
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3852, 3858, 3847, 3850	0	928	0.01
Jan 31	3829, 3838, 3822, 3823	0	296	0
Feb 28	3830, 3830, 3820, 3828	0	10	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	43485, 43700, 43410, 43507	407.04	11173	411.18
May 05	43906, 44150, 43906, 44025	1.71	54	6.09
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	43530, 43720, 43451, 43535	36.91	25081	35.48
Apr 30	44053, 44235, 43969, 44059	1.16	933	1.57
Jun 30	44465, 44590, 44465, 44528	0	2	0.01
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	43522, 43724, 43435, 43528	125.26	19067	61.44
Apr 30	44035, 44220, 44000, 44040	1.37	265	1.36

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	157.8, 162.7, 156.3, 160.8	134561mb	59603	30879mb
Jan 28	159, 162.9, 158.8, 161.4	8356mb	4787	10923mb
Feb 25	157.6, 160.3, 157.1, 159.4	1016mb	751	2874mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Dec 18	4191, 4214, 4152, 4195	24851bl	123638	1901bl
Jan 17	4192, 4217, 4158, 4198	814bl	5860	262bl
Feb 19	4170, 4215, 4170, 4192	0bl	3	0bl
Crude Oil Mumbai MCX(1 Bl)				
Dec 18	4195, 4213, 4151, 4196	5870bl	232348	401bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

संक्षेप में

750 करोड़ रु.के निर्गम के दस्तावेज की अनुमति

साढ़े सात सौ करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने वाली कंपनियां अब बाजार नियामक सेबी के क्षेत्रीय कार्यालयों में निर्गम से जुड़े मसौदा दस्तावेज जमा कर सकती हैं। अभी तक, कंपनियों की ओर से उनके मर्चेंट बैंकरों को 500 करोड़ रुपये तक के निर्गम के लिए सेबी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में दस्तावेज जमा करने की अनुमति है। सेबी ने कहा कि 750 करोड़ रुपये से अधिक के निर्गम के लिए कंपनी को नियामक के मुख्यालय में मसौदा दस्तावेज जमा करना होगा। सेबी के चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें कंपनियां निर्गम पेशकश से जुड़े दस्तावेज जमा कर सकती हैं। नया नियम बुधवार से लागू होगा। *भाषा*

डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे मजबूत

घरेलू शेयर बाजारों में तेजी और कच्चे तेल के दाम में नरमी के साथ रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे मजबूत होकर 70.85 पर पहुंच गया। यह लगातार छठा सत्र है जब रुपया मजबूत हुआ है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार गुरुवार को जारी होने वाले मुद्रास्फीति तथा औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े से पहले रुपये में तेजी आई है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपये 70.87 पर खुला। *भाषा*

हिस्सेदारी बिक्री मुद्दे पर अदालत पहुंची बिडवेस्ट

कंपनी का कहना है कि इस हिस्सेदारी बिक्री के मामले के समाधान में अगर विलंब होता है तो इससे उसका हित प्रभावित होगा

देव चटर्जी
मुंबई, 11 दिसंबर

मुंबई हवाई अड्डा अधिग्रहण विवाद सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित मध्यस्थता पैनल से 15 दिसंबर तक हवाई अड्डे में बिडवेस्ट की 13.5 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री पर निर्णय लेने को कहा है।

जीवीके समूह की याचिका की वजह से इस साल जनवरी में अदाणी समूह को अपनी हिस्सेदारी बेचने में विलंब से चिंतित बिडवेस्ट ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मध्यस्थता पैनल से इस मामले में रविवार तक फैसला लेने को कहा है। न्यायालय इस मामले पर 13 जनवरी को फिर से सुनवाई करेगा।

बिडवेस्ट की ओर से अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि यदि मामले में और विलंब होता है तो संभावित खरीदार (अदाणी समूह) सौदे से पीछे हट सकता है। बिडवेस्ट का कहना है कि जीवीके समूह के पास उसके शेयर खरीदने के लिए पूंजी नहीं है और इस मामले के समाधान में अगर किसी तरह का विलंब होता है तो इससे उसका हित प्रभावित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, 'हमने आर्बिट्रेशन ऐंड कंसिलिएशन ऐक्ट, 1996 की धारा 17 के तहत दायर मामले के निपटारा मध्यस्थता पैनल से अगली सुनवाई (15 दिसंबर, 2019) तक करने को कहा है।' इस मामले की 13 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी।

जीवीके को हिस्सेदारी बिक्री के लिए आरओएफआर (राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल) समझौते के तहत बिडवेस्ट ने जनवरी में मायल में अपनी हिस्सेदारी अदाणी समूह को बेचने के लिए सौदा किया था। जीवीके समूह 30 दिन की समय-सीमा के अंदर हिस्सेदारी खरीदने में नाकाम रहा और मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में चला गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने हिस्सेदारी खरीदने के लिए और समय मांगने के जीवीके के अनुरोध को ठुकरा दिया। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने इस साल जुलाई में यह मामला मध्यस्थता पैनल को सुपुर्द कर दिया जो तब से इसकी सुनवाई कर रहा है।

27 अक्टूबर को, जीवीके ने घोषणा की थी कि वह हवाई अड्डा व्यवसाय में 79.1 प्रतिशत हिस्सेदारी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, पीएसपी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कनाडा, और नैशनल इन्वेस्टमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड को बेचकर 7,614 करोड़ रुपये जुटाएगी।

जीवीके द्वारा इस सौदे से प्राप्त रकम का इस्तेमाल अपनी होल्डिंग कंपनियों का लगभग 5,500 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने और मायल में दक्षिण अफ्रीकी कंपनियों (बिडवेस्ट और एयरपोर्ट्स कंपनी साउथ अफ्रीका) से अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने पर खर्च किया जाना था। लेकिन नियामकीय मंजूरियों में विलंब की वजह से सौदे में विलंब हुआ। फिलहाल इस बारे में अदाणी समूह के प्रवक्ता ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है।

हालांकि अदाणी समूह के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि उनके पास बिडवेस्ट की हिस्सेदारी खरीदने के लिए रकम तैयार है और यह सौदा एक सप्ताह के अंदर हो सकता है। इससे पहले, अदाणी समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि समूह ने मायल में सभी हिस्सेदारी खरीदने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की पूंजी निर्धारित की है।

- अपनी हिस्सेदारी बेचने में विलंब से चिंतित बिडवेस्ट ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
- न्यायालय ने मध्यस्थता पैनल से 15 दिसंबर तक बिडवेस्ट की हिस्सेदारी पर निर्णय लेने को कहा
- सर्वोच्च न्यायालय इस मामले पर 13 जनवरी को फिर से सुनवाई करेगा

मायल में हिस्सेदारी

जीवीके समूहः	50.5 %
बिडवेस्टः	13.5 %
एयरपोर्ट कंपनी, एसएः	10 %
एएआईः	26 %

निवेशकों ने बेहतर प्रदर्शन खुलासे की मांग की

सचिन मामबटा
मुंबई, 11 दिसंबर

एक निवेशक संगठन ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को पत्र लिखकर पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (पीएमएस) प्रदाताओं के प्रदर्शन पर बेहतर जानकारी मुहैया कराने को कहा है। इसके बाद नियामक ने इस सेगमेंट से संबंधित मानकों में बदलाव लाने पर ध्यान दिया है।

पीएमएस उद्योग उन अमीर निवेशकों की जरूरतें पूरी करता है जो ऐसी योजनाओं के लिए बड़ी रकम लगा सकते हैं और अक्सर इन्हें योजनाओं को म्युचुअल फंडों (एमएफ) की तुलना में ज्यादा जोखिम वाला माना जाता है। एक डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो प्रबंधक परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधन करता है। वहीं नॉन-डिस्क्रेशनरी प्रबंधन ग्राहक के निर्देश के आधार पर कार्य करता है।

एमएफ के विपरीत इन योजनाओं के बारे में सीमित जानकारी होती है। वहीं म्युचुअल फंड अपने प्रदर्शन की दैनिक जानकारी मुहैया कराते हैं।

मिडास टच इन्वेस्टर्स एसोसिएशन द्वारा लिखे गए पत्र (जिसकी प्रति बिजनेस स्टैंडर्ड के पास उपलब्ध है) में कहा गया है, 'दुर्भाग्यवश, यह आंकड़ा चरणबद्ध स्वरूप में मौजूद नहीं है। यह न तो सेबी की वेबसाइट पर और न ही पोर्टफोलियो प्रबंधकों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।'

इसमें लुप्त हुईं कंपनियों के मुद्दे पर अतिरिक्त कदम उठाने को भी कहा गया है। संगठन का कहना है कि निवेशकों से पूंजी जुटाने वाली कम से कम 752 कंपनियों का कोई अस्तित्व नहीं है।

लुप्त कंपनियों की पहचान के लिए कई प्रयास किए गए हैं, और इसकी एक सूची बनाई गई है। मिडास टच इन्वेस्टर्स एसोसिएशन के संस्थापक वीरेंद्र जैन का कहना है कि सूची तैयार होने के बावजूद ऐसी कंपनियों में निवेशकों की शिकायतों को दूर करने के लिए सख्त कदम नहीं उठाया गया है।

संगठन ने निर्धारित समय-सीमा के अंदर 752 फर्जी कंपनियों और उनके प्रवर्तकों तथा निदेशकों की परिसंपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई का अनुरोध किया है।

उसने यह भी सुझाव दिया है कि पीएमएस प्रदाताओं के लिए नेटवर्थ और निवेश आकार बढ़ाने के मुद्दे को अलग तरीके से संभाला जा सकता था, क्योंकि इससे बाजार पर दबाव पड़ सकता है।

पूंजी बाजार नियामक ने अपनी 20 नवंबर की बैठक में यह निर्णय लिया था कि पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के लिए नेटवर्थ 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये की जानी चाहिए। न्यूनतम निवेश आकार भी 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया। नियामक ने डिस्क्रेशनरी पोर्टफोलियो प्रबंधकों को सिर्फ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों और अन्य विशेष योजनाओं में निवेश करने की जरूरत जैसे बदलाव भी किए।

नॉन-डिस्क्रेशनरी या एडवायजरी पोर्टफोलियो प्रबंधक गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में एक-चौथाई से ज्यादा परिसंपत्तियों का निवेश नहीं कर सकते।

एक पोर्टफोलियो प्रबंधक ने कहा कि पीएमएस प्रदाताओं द्वारा आंकड़ा उपलब्ध कराने के तौर-तरीकों में समानता का अभाव है। कुछ प्रदाता सिर्फ मॉडल पोर्टफोलियो का प्रतिफल मुहैया कराते हैं, जबकि अन्य सिर्फ खास निवेशकों के बारे में जानकारी देते हैं। पीएमएस मानकों पर कार्य समूह की ताजा रिपोर्ट में प्रदर्शन खुलासों के मानकीकरण का प्रस्ताव रखा गया है।

पारदर्शिता की मांग

- प्रदर्शन संबंधी जानकारियों के स्वरूप में भिन्नता है
- इससे निवेशकों को प्रदर्शन का आकलन करने में समस्या होती है
- नियामक को लिखे पत्र में पीएमएस प्रदाताओं से समान आंकड़ा सुनिश्चित करने को कहा गया है

युवाओं में लोकप्रिय होंगे टाइटन के परफ्यूम

पवन लाल
मुंबई, 11 दिसंबर

टाइटन इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाले फास्ट्रैक ब्रांड ने इत्र बाजार में दस्तक दी है। इस ब्रांड की उपस्थिति मौजूदा समय में घड़ी, बेल्ट और वॉलेट के क्षेत्र में है।

ब्रांड की लोकप्रियता को देखते हुए टाइटन को उम्मीद है कि ये नए इत्र देश में युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय होंगे। फास्ट्रैक ब्रांड को वर्ष 1998 में शुरू किया गया था और यह पूरे देश में 79 शहरों में 173 विशेष स्टोरों तथा अधिकृत मल्टी-ब्रांड आउटलेटों के जरिये बिक्री करता है। ब्रांड की ऑनलाइन उपस्थिति भी है।

फास्ट्रैक घड़ी सेगमेंट ने लगभग 9 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की है और टाइटन के कुल राजस्व में इसका करीब 35 प्रतिशत योगदान है।

इत्र की नई रेंज फास्ट्रैक परफ्यूम्स के तहत बेची जाएगी और यह 6 अलग अलग वैरिएंट में होगी। ये परफ्यूम टाइटन की मिड-लेवल लाइन 'स्किन परफ्यूम्स' से कम कीमत के होंगे। स्किन परफ्यूम्स हर साल लगभग 15 लाख बोतलों की बिक्री करती है जिससे टाइटन के राजस्व में लगभग 120 करोड़ रुपये का इजाफा होता है। यह परफ्यूम दो अंक की वृद्धि दर्ज कर रहा है।

एक्सेसरीज खंड के लिए टाइटन के मुख्य परिचालन अधिकारी मनीष गुप्ता ने कहा, 'फास्ट्रैक परफ्यूम का अल्पावधि में टाइटन की फ्रेगरेंस बिक्री में लगभग एक-तिहाई योगदान रहने का अनुमान है। फास्ट्रैक युवाओं के बीच मजबूत संभावनाओं की वजह से कुछ वर्षों में बिक्री के संदर्भ में स्किन को पीछे छोड़ सकता है।'

अनन्या पांडे को ब्रांड के साथ जोड़ने वाला फास्ट्रैक परफ्यूम्स 16 से 21 वर्ष उम्र के युवाओं की जरूरतें पूरी करेगा। इसकी उत्पाद रेंज 835 रुपये से 995 रुपये के बीच मौजूद है। ये परफ्यूम पुरुष और महिलाओं दोनों की जरूरत पूरी करते हैं और इन्हें अंतरराष्ट्रीय परफ्यूम घरानों गिवेडन और फरमेनिच द्वारा विकसित किया गया है और गुजरात के वापी में अनुबंध निर्माताओं के साथ भागीदारी के जरिये निर्मित किया गया है।

गुप्ता ने कहा, 'मौजूदा समय में, फ्रेगरेंस श्रेणी में खपत भारत के प्रमुख 10 शहरों पर केंद्रित है जो सामान्य तौर पर महानगरीय इलाके हैं, लेकिन हमें भविष्य में अन्य 10 उभरते बाजारों से इस खपत में तेजी आने की संभावना है।' बाजार विश्लेषकों का कहना है कि चंडीगढ़ और गुवाहाटी अन्य ऐसे शहर हैं जहां परफ्यूम व्यवसाय में तेजी दर्ज की गई है। रिसर्च ऐंड मार्केट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय परफ्यूम और डियोड्रेंट बाजार वर्ष 2018 में 79 करोड़ डॉलर का था। वर्ष 2024 तक इसके 17 प्रतिशत की सालाना चक्रवृद्धि दर के साथ बढ़कर 2.4 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इस व्यवसाय को तेज शहरीकरण और ऑनलाइन रिटेल के विकास से मदद मिलने की संभावना है।

दुबई स्थित स्पेशियल्टी परफ्यूमरी अजमल ऐंड संस में परिचालन अध्यक्ष सौरव भट्टाचार्य का कहना है कि मौजूदा समय में 'लुक गुड', 'फील गुड', और 'स्मेल गुड' सभी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं।

- फास्ट्रैक परफ्यूम्स ब्रांड 16 से 21 वर्ष उम्र के युवाओं की जरूरतें पूरी करेगा
- ब्रांड की उत्पाद रेंज 835 रुपये से 995 रुपये के बीच मौजूद है

भारत में पहचान बनाएगी वर्जिन अटलांटिक

अनीश फडणीस
मुंबई, 11 दिसंबर

वर्जिन अटलांटिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन को चुनौतियां पसंद हैं। 69 वर्ष की उम्र में क्रूजलाइन पेश करने वाले ब्रैनसन अंतरिक्ष यान में परीक्षण उड़ान की तैयारी कर रहे हैं और भारत-ब्रिटेन बाजार में प्रमुख एयरलाइनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

वर्जिन अटलांटिक लंदन-मुंबई मार्ग पर दो बार विफल साबित हो चुकी है, लेकिन ब्रैनसन को उम्मीद है कि एयरलाइन तीसरी बार भाग्यशाली रहेगी, क्योंकि उसने जेट एयरवेज के बंद होने के बाद हवाई यातायात में वृद्धि और अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस के साथ अपनी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया है।

ब्रिटेन की इस एयरलाइन ने अक्टूबर में अपनी मुंबई उड़ान पुनः शुरू की है और वह अगले साल मार्च से लंदन-दिल्ली की दूसरी उड़ान शुरू करेगी। नई उड़ानों के संदर्भ में मुंबई आए ब्रैनसन ने एयर इंडिया में निवेश की संभावना से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने 15 मिनट में मुंबई-पुणे को जोड़ने के लिए हाइपरलूप में निवेश की योजना बनाई है और वह इस परियोजना पर सहमति के लिए गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा, 'सरकार से किसी तरह की वित्तीय राहत मिलने की संभावना नहीं है। यह पूरी तरह निजी निवेश होगा और लोगों को हाइपरलूप के तुरंत बाद लाभ मिलने लगेगा।'

जहां भारत-ब्रिटेन के बीच हवाई यातायात बढ़ा है, वहीं जेट एयरवेज के बंद होने से बाजार में क्षमता घटी है जिससे वर्जिन अटलांटिक को सेवाएं पुनः शुरू करने के लिए अवसर पैदा हुए हैं। मौजूदा समय में इन दो देशों के बीच मार्ग पर हवाई यातायात में एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज और एमिरेट्स का दबदबा है।

एयरलाइन के कार्यकारी उपाध्यक्ष जुहा जर्वीनेन ने कहा, 'हमारी उड़ानें लगभग पूरी क्षमता दर्ज कर रही हैं और हमें शानदार प्रतिफल की उम्मीद है। हम यहां मजबूती के साथ डटेंगे। दूसरी दिल्ली उड़ान भारतीय बाजार के लिए हमारी प्राथमिकता है।' एयरलाइन मैनचेस्टर को भारत के साथ जोड़ने की भी संभावना तलाश रही है। जेट एयरवेज के साथ वर्जिन अटलांटिक की मजबूत वाणिज्यिक भागीदारी थी। जेट ने अप्रैल में अपना परिचालन बंद कर दिया।

- वर्जिन अटलांटिक की भारत-लंदन के बीच अगले साल गर्मी में तीन दैनिक उड़ानें होंगी
- सितंबर तक की 12 महीने की अवधि में लगभग 34 लाख यात्रियों ने भारत-ब्रिटेन के बीच यात्रा की
- एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज और ऐमिरेट्स भारत-ब्रिटिश बाजार में सबसे बड़ी एयरलाइन हैं